● वर्ष-2
● अंक-160
रायपुर, बुधवार
22 फरवरी 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

इन दिनों

✍ शशांक शर्मा

घोटाले के खिलाफ कार्रवाई पर उठते सवाल

भारतीय जनता पार्टी बार-बार प्रदेश की भूपेश सरकार पर आरोप लगाती है कि छत्तीसगढ़ को ईडी और सीडी मामले ने बदनाम कर दिया है। पिछले लगभग 3 वर्षों से प्रदेश के बड़े अधिकारियों, कारोबारियों और नेताओं पर छापा मारने का एक लंबा सिलसिला है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी जब प्रदेश के उच्च अधिकारियों के घर पर आयकर विभाग ने दबिश देकर सर्वे किया था। इस कार्रवाई में कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सहित बड़ी मात्रा में दस्तावेज जब्त कर विभाग अपने साथ ले गया। उसके बाद प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एन्ट्री हुई। अभी जब अखिल भारतीय कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन रायपुर में होने वाला है उसके ठीक पहले ईडी ने प्रदेश के 12 कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा है। इस घटना ने पूरे देश में एक राजनीतिक सनसनी पैदा कर दी है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक कांग्रेस पार्टी ईडी की कार्यवाही को राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन में व्यवधान उत्पन्न करने का षड्यंत्र बताया। यह बात सही है जब किसी राष्ट्रीय पार्टी का एक अति महत्वपूर्ण महाधिवेशन होने जा रहा हो जिसमें पूरे देश से दिग्गज कांग्रेसी नेता आ रहे हों उसके ठीक पहले इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे नेताओं के ठिकानों पर छापा मारना समय की दृष्टि से सही नहीं है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अगर राजनीतिक निर्देश के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है तो कम से कम किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम के पहले छापेमारी नहीं की जाती। इससे ऐसा लगता है कि छापेमारी का निर्णय ईडी के अधिकारी ले रहे है जो राजनीति के महत्व को नहीं समझते। अगर ईडी के पास पुख्ता सबूत और जानकारियां है तो छापा मारने के लिए कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन के संपन्न हो जाने की प्रतीक्षा भी कर सकते थे। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी भी आक्रमक मूड में आ गई है। पहले तो जिन नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की गई वहां कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच कर विरोध जताने लगे तो दूसरी ओर मंगलवार को ईडी के कार्यालय का कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने घेराव किया। इधर मुख्यमंत्री सहित पार्टी के नेता ईडी की कार्रवाई के खिलाफ बयान भी दे रहे है। मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे है कि ईडी की कार्यवाही कांग्रेस पार्टी और गैर भाजपाई दलों के नेताओं के खिलाफ ही क्यों हो रही है। उन्होंने भाजपा के नेताओं की काली कमाई की ओर भी उंगली उठाई है जिसके खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वैसे इस बात में दम तो है क्योंकि देशभर के भाजपा के नेताओं ने भी जब मौका मिला तो मोटी कमाई की है। लेकिन आंकड़े के मुताबिक पिछले 8 वर्षों में ईडी ने 5 हजार से अधिक छापामार की है जिसमें से 90 प्रतिशत गैर भाजपाई दल के नेता है। लेकिन प्रदेश में ईडी की कार्रवाई के बाद एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कारोबारी गिरफ्तार है और उनके खिलाफ में कोर्ट में चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है। इन दस्तावेजों में ईडी ने बहुत स्पष्टतौर पर अधिकारियों, कारोबारियों और नेताओं के बीच कोयले के कारोबार में कथित अवैध लेनदेन का साक्ष्य सहित विवरण किया है। इसी आधार पर गिरफ्तार किए गए अधिकारियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि कोयले के कारोबार में सैकड़ों करोड़ रुपए का अवैध लेनदेन तो हुआ है। अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हों तो भ्रष्टाचार पर नकेल कैसे डाल सकेंगे? इसका मतलब है कि ईडी की कार्रवाई सही है और इस कार्रवाई में 540 करोड़ रुपए के घोटाले को भी कोई झुठला नहीं रहा है। बात केवल छापे के समय और चिन्हित राजनीतिक पार्टी और नेताओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे है। ईडी की जांच अब उस स्तर तक पहुंच चुकी है जब कोयला सहित शराब और अन्य कारोबार में हुई गड़बड़ियों का खुलासा होगा और कई अधिकारी, कारोबारी और प्रमुख नेता जांच के लपेटे में आएंगे। यह तो स्पष्ट हो गया है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार और ईडी की कार्रवाई प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है। इसके साथ राजनीतिक कटुता भी बढ़ रही है जो बयान की मर्यादाओं को लांघ रही है।

कांग्रेस नेताओं के घर देर रात तक चली कार्रवाई

कोयला लेवी घोटाले से जोड़े जा रहे हैं तार, कांग्रेस पार्टी ईडी पर हमलावर हुई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के घर सोमवार सुबह शुरू हुई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई देर रात खत्म हो गई। दिनभर की जांच पड़ताल के बाद कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह को ईडी अपने साथ ले गई। दरअसल, ईडी ने यह छापा इसलिए मारा है क्योंकि उन्हें कोयला लेवी घोटाले में इन नेताओं के नाम से पैसों की एंट्री मिली है। ईडी अपनी कार्रवाई में यह जांच रही है कि इन नेताओं के पास पैसे क्यों और कैसे पहुंचे। कोयला लेवी घोटाले मामले में इनकी क्या भूमिका है।

दिनभर चली पूछताछ और तलाशी अभियान के बाद ईडी के अफसर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह को लेकर बाहर निकले। इस बीच उनके घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने उन्हें घेर लिया। उपाध्याय का कहना था कि इतनी पूछताछ के बाद बिना किसी तथ्य के अधिकारी आरपी सिंह को नहीं ले जा सकते। हालांकि अधिकारियों के काफी समझाने-बुझाने के बाद विकास आरपी सिंह को ले

जाने देने को तैयार हुए। इस बीच हाउसिंग बोर्ड के सदस्य विनोद तिवारी के घर पर तलाशी ले रही ईडी की टीम भी लौट आई ।

ईडी की कार्रवाई खत्म होने के बाद विनोद तिवारी ने घर के भीतर की एक तस्वीर जारी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता से घबराहट, केंद्र के इशारे पर कुटरचित डायरी के पन्ने, महाधिवेशन का डर, आज ईडी पहुंची मेरे घर। सुबह से शाम तक ली मेरे घर की तलाशी। रमन सिंह की आय से संबंधित पेपर घर पर थे। ईडी के अधिकारी पेपर अपने साथ क्यों नहीं ले गये। ईडी रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी।

इधर, ईडी की टीम देर रात तक रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय के घर पर तलाशी कर ही रही थी। तलाशी के दौरान रामगोपाल अग्रवाल अपने घर पर मौजूद नहीं थे। इस बीच ईडी की ओर से कार्रवाई पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव घर के बाहर आधी रात के बाद भी हंगामा जारी रहा। देवेंद्र यादव ने रात करीब 11.30 बजे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा, जिस आत्मविश्वास के साथ आप बाहर डटे हो उसी आत्मबल से मैं अंदर डटा हूं। वादा करता हूं साथियों, न आपका विश्वास टूटेगा न मेरा आत्मबल टूटेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है।

क्यों और कैसे पहुंचे पैसे

छत्तीसगढ़ के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले साल ईडी ने कोयला लेवी घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ में छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान नेता, कारोबारी और आईएएस अफसरों के घर छापे मारे गए थे। इस रेड के दौरान ईडी के हाथ कुछ दस्तावेज लगे थे। इसमें कुछ कांग्रेस नेताओं को पैसे दिए जाने की एंट्री का रिकॉर्ड मिला था। दरअसल, यह पैसों की एंट्री उस समय की है जब प्रदेश में ढाई-ढाई साल के सत्ता परिवर्तन के मामले में बवाल चल रहा था। और दिल्ली में भूपेश बघेल समर्थक विधायक उन्हें सीएम बनाए रखने की मांग लेकर कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंचे थे। इस दौरान कुछ विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी पर्दे के पीछे से विधायकों को मैनेज कर रहे थे। सोमवार को ईडी ने इन्हीं नेताओं और विधायकों के घर छापामार कार्रवाई की है। क्योंकि पैसों की एंट्री में इन विधायकों के नाम शामिल हैं। ईडी अपनी कार्रवाई में यह जांच रही है कि इन नेताओं के पास पैसे क्यों और कैसे पहुंचे और कोयला लेवी घोटाले मामले में इनकी क्या भूमिका है। बताया जाता है कि जिन नेताओं का नाम एंट्री में मिला है, उनका सीधे तौर पर कोयला लेवी मामले से कोई लेना-देना नहीं हैं। लेकिन यह एंट्री विधायकों को मैनेज करने के लिए जुटाए गए फंड की हो सकती है।

कहां-कहां पड़े छापे

निदेशालय ने रायपुर की श्रीराम नगर, डीडी नगर, गीतांजलि नगर, मोवा पर छापे मारे हैं। इनमें प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सत्ती अग्रवाल, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के ठिकाने शामिल हैं। इसके साथ ही भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव और उनके भाई धर्मेंद्र यादव के ठिकानों पर पर कार्रवाई हुई है। तीन दिन बाद यानी 24 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होना है। इसमें सोनिया गांधी और राहुल समेत देशभर से कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। इससे पहले ईडी ने छापे मारे हैं। इस कारण इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस नेता तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

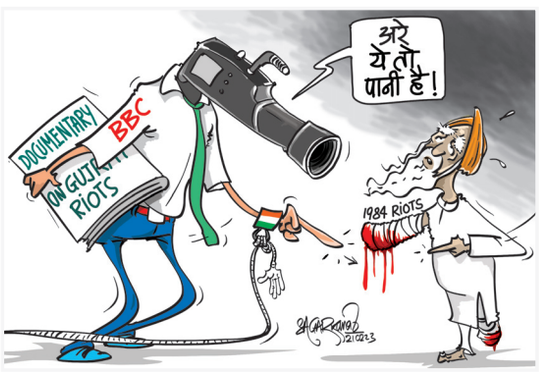

1984 पर कोई डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं : जयशंकर

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि ये (बीबीसी डॉक्यूमेंट्री) अचानक आया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि चुनाव का समय भारत और दिल्ली में शुरू हुआ हो या नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में जरूर शुरू हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल कर राजनीति की जा रही है। एस जयशंकर ने कहा कि वे खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि हम एक एनजीओ, मीडिया

संगठन आदि हैं, लेकिन वे राजनीति कर रहे हैं। कई बार भारत में चल रही राजनीति यहां की नहीं बल्कि भारत से आई होती है। विचार और एजेंडा बाहर से आए होते हैं। आप डॉक्यूमेंट्री ही बनाना चाहते हैं तो दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ था। हमें उस विषय पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली? उन्होंने कहा कि आप किसी के मान सम्मान को धक्का पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि ये सत्य के लिए केवल एक खोज है, जिसे हमने 20 साल बाद इस समय पर लाने का फैसला किया है।

चीन की आक्रामकता को लेकर सरकार पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि यह कांग्रेस नेता नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने वास्तविक रेखा पर सेना भेजी थी। चीन द्वारा सेना की तैनाती के जवाबी उपाय के रूप में नियंत्रण और विपक्षी दल को 1962 में जो कुछ हुआ उसे देखने के लिए ईमानदारी रखनी चाहिए।

प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल 23 फरवरी को लेंगे शपथ

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन कल 22 फरवरी को राजभवन विजयवाड़ा, आंध्रप्रदेश से प्रात: 7:40 बजे प्रस्थान करेंगे तथा प्रात: 8:30 बजे विशेष विमान से रवाना होकर प्रात: 10:00 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल, रायपुर पहुंचेंगे। तत्पश्चात वे राजभवन के लिए प्रस्थान करेंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन 23 फरवरी 2023 को प्रात: 11.30 राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल को बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अरूप कुमार गोस्वामी शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधिगण, आमंत्रित गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

गैंगस्टर-आतंकवादी गठजोड़ मामले में एनआईए ने मारे देशभर के 72 ठिकानों पर छापे

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) गैंगस्टर-आतंकवादी गठजोड़ पर एक बड़ी कार्रवाई में कई राज्यों में 72 स्थानों पर छापेमारी कर रही है।राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) देशभर में 72 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में एनआईए के अधिकारी पीलीभीत में एक हथियार सप्लायर के घर पर छापेमारी कर रहे हैं. एनआईए सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान से सप्लाई किए गए ये हथियार छापेमारी के दौरान मिले हैं।सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना गिरोह के दर्जनों गैंगस्टरों से पूछताछ की थी और पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई थी। मंगलवार को छापेमारी के दौरान कई हथियार बरामद हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने पाकिस्तान के आईएसआई और गैंगस्टर गठजोड़ पर इनपुट इकट्ठा किया है और गैंगस्टर मामले में अब तक चार दौर की छापेमारी कर चुकी है। कई गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया है और कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सीबीआई ने एफसीआई भ्रष्टाचार मामले में पंजाब में 30 स्थानों पर छापे मारे

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने व्यापारियों और चावल मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए घटिया अनाज खरीदने वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में मंगलवार को पंजाब में 30 स्थानों पर छापेमारी शुरू की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई की टीमों ने ऑपरेशन कनक 2 के तहत सरहिंद, फतेहपुर साहिब और मोंगा सहित पंजाब के कई जिलों में अनाज व्यापारियों, चावल मिल मालिकों और एफसीआई के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों के परिसरों पर छापे मारे। एफसीआई में अधिकारियों के एक संगठित समूह से संबंधित प्राथमिकी के सिलसिले में दूसरी बार छापे मारे गए हैं। आरोप है कि इस समूह ने निजी मिल मालिकों द्वारा आपूर्ति किए गए कम गुणवत्ता वाले अनाज और अन्य फायदों पर पर्दा डालते हुए प्रति फसल सीजन एफसीआई गोदामों में उतारे गए प्रति ट्रक पर 1000-4000 रुपये रिश्वत ली। बार में रिश्वत की राशि को निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों के बीच वितरित किया गया।

उत्तराखंड में भी भूकंप मचा सकता है तुर्की जैसी तबाही! मिल रहे संकेत

देहरादून। तुर्की में भूकंप के भीषण तबाही मचाने के बाद अब उत्तराखंड क्षेत्र में भी भूकंप आने की आशंका जाहिर की गई है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) में भूकंप विज्ञान के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. एन. ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तुर्की से भी बड़े भूकंप का खतरा उत्तराखंड पर मंडरा रहा है। राव ने टीओआई को बताया कि उत्तराखंड क्षेत्र में सतह के नीचे बहुत तनाव पैदा हो रहा है। राव ने जोर देकर कहा कि हम सटीक समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन उत्तराखंड में कभी भी भारी भूकंप आ सकता है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड पर केंद्रित हिमालयी क्षेत्र में लगभग 80 भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए हैं। हम वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हमारा डेटा दिखाता है कि तनाव काफी समय से जमा हो रहा है। हमारे पास क्षेत्र में जीपीएस नेटवर्क हैं। जीपीएस पॉइंट्स हिल रहे हैं, जो सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं।

पुतिन ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि को किया निलंबित

मोस्को। रूस ने अमेरिका के साथ एकमात्र परमाणु संधि को भी निलंबित कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नई स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है जो दोनों पक्षों के सामरिक परमाणु शस्त्रागार को सीमित करता है। पुतिन ने संसद में एक प्रमुख भाषण के अंत में सांसदों से कहा कि इस संबंध में, मुझे आज यह घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन में युद्ध में लगभग एक वर्ष की समाप्ति के मौके पर पुतिन ने कहा कि रूस सामरिक आक्रामक हथियार संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है। 2010 में प्राग में नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के ठीक बाद पांच और वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा तैनात किए जा सकने वाले रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या और उन्हें वितरित करने के लिए भूमि और पनडुब्बी आधारित मिसाइलों और बमवर्षकों की तैनाती को सीमित करता है।

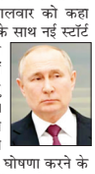

नीतीश विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं पर उन पर भरोसा कौन करे?

राजेश बादल

बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने दो दिन पहले एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में सौ सीटों के भीतर समेटना हो तो विपक्ष को एकजुट होना आवश्यक है और कांग्रेस को इसमें आगे आना होगा। जिस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने यह बात कही, उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी थे। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस आलाकमान तक नीतीश कुमार की भावना पहुंचा देंगे। पर उन्होंने जोड़ा कि देखने वाली बात यह है कि आई लव यू कहने की पहल किसकी ओर से होगी।

कांग्रेसी वोट बैंक के बिखरने से अपने दल का वोट बैंक बनाने वाले दल भी अब उसी कांग्रेस पर विपक्षियों को एकजुट करने की जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। यानी वे मानने लगे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस ही ऐसा दल है, जिसके बैनर तले विपक्षी एकता फल-फूल सकती है। जहां तक प्रतिपक्ष की एकजुटता का प्रश्न है तो सैद्धांतिक और वैचारिक आधार पर किसी भी ध्रुवीकरण का संसदीय लोकतंत्र में विरोध क्यों कर होना चाहिए? समान विचार वाले राजनीतिक दलों का एक मंच पर आना एकदम स्वाभाविक माना जा सकता है। लेकिन अफसोस यह है कि ऐसा होता नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष के एकजुट होने का अर्थ सत्ताधारी दल या उसके नेता को पटखनी देना ही माना जाता रहा है।

1977 में धुर विरोधी वैचारिक आधार वाले राजनीतिक दल जनता पार्टी के झंडे तले एक हुए थे तो उनका एकमात्र उद्देश्य इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करना था। इसके बाद वह एकता तीन साल में ही बिखर गई। विपक्ष के एक होने का उदाहरण तब देखने को मिला, जब राजीव गांधी को हटाने के लिए आंदोलन छेड़ा गया था। इस मामले में भी सैद्धांतिक धरातल पर परस्पर विरोधी पार्टियों ने विश्वनाथ

प्रताप सिंह को समर्थन दिया था। क्या कोई भरोसा कर सकता है कि भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियां राजीव विरोध के कारण ही वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रही थीं। कांग्रेस के विरोध में बनी यह एकता भी दो वर्ष में छिन्न-भिन्न हो गई। इसके बाद मुल्क ने सियासी अस्थिरता का दौर देखा और एनडीए तथा यूपीए गठबंधनों का युग आया। एकाध अपवाद छोड़ दें तो अधिकतर छोटी मंझोली पार्टियां अपने-अपने हितों के आधार पर एकजुट होती रहीं या तमाम खेमों में आती जाती रहीं। स्वस्थ लोकतंत्र के सरोकार हाशिये पर जाते रहे। जब तक किसी पार्टी का स्वार्थ सधता, वह गठबंधन का पल्लू पकड़कर रखती। जब उसकी बात नहीं सुनी जाती तो लोकतंत्र की दुहाई दे वह गठबंधन को ठेंगा दिखाते बाहर चली जाती। असल में यह लोकतंत्र के विद्रुप उपहास का दौर चल रहा है। जो नीतीश कुमार आज कांग्रेस के छाते के नीचे एकजुट होने की बात कर रहे हैं और भाजपा को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं, वे एक-दो बार नहीं, तीन बार उसी भाजपा के साथ गलबहियां डालकर सरकार बना चुके हैं। पिछली बार तो उन्हें जनादेश ही कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाने का मिला था। उसका अपमान कर नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ जाकर मिल गए थे। जब भाजपा ने साथ होते हुए भी नीतीश की पार्टी को कमजोर बनाने का काम किया और विधानसभा चुनाव में उनकी अपनी पार्टी अत्यंत दुबली हो गई तो उनकी आंखें खुलीं। उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया।

जाहिर था कि यह सिद्धांतों के आधार पर नहीं, स्वार्थों के आधार पर बना गठबंधन था। टिकाऊ विपक्षी एकता के लिए लोकतांत्रिक और नैतिक उसूलों की जरूरत होती है, निजी हितों की नहीं। यह बात उन राजनेताओं को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए जो स्वार्थ के कारण गठबंधन करते हैं और जम्हूरियत की दुहाई भी देने लगते हैं। मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेसी संस्कारों में पले-बढ़े। जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, जिसे वे घनघोर सांप्रदायिक पार्टी बताते रहे हैं। आज उनका गुट भाजपा में तेल-पानी के संगम जैसा है, जो कभी नहीं मिलते।

स्पष्ट है कि जब तक राजनीतिक दल और नेता सिद्धांतों की खातिर सत्ता छोड़ना नहीं सीखते और स्वार्थों के कारण सत्ता से चिपकना नहीं छोड़ते , तब तक कोई भी एकता अमिट और स्थायी नहीं रह सकती। यह नकारात्मक राजनीति है कि किसी राजनेता को हटाने के लिए गठबंधन बनाए जाएं। अतीत के उदाहरण गवाह हैं कि ऐसे गठजोड़ कम आयु के होते हैं। अगर यह जारी रहते हैं तो लोकतंत्र के लिए घातक हैं। आने वाले समय में चेतावनी के रूप में प्रस्तुत रहेंगे। चेतावनी से अर्थ यह है कि नीतीश कुमार और उनकी आयु वर्ग के वर्तमान नेताओं की यह आखिरी पीढ़ी है। जब यह पीढ़ी सिद्धांतों और सरोकारों को ताक में रखती है और मूल्यविहीन राजनीति करती है तो वह देश का मखौल उड़ाती दिखाई देती है। यही नहीं, वह आने वाली नस्लों को भी बिगाड़ने का काम कर रही है।

नौजवान खून इसी को सियासत समझता है। इस तरह पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकृत सियासी संस्कारों की फसल उपजती रहती है। देश की लोकतांत्रिक सेहत को नुकसान पहुंचता रहता है। विपक्षी एकता इससे अछूती नहीं रह सकती। जब पराजित पार्टी गठबंधन के दलों को उनके हित साधने की गारंटी देगी तो उन्हें पाला बदलने में देर नहीं लगेगी। नीतीश कुमार स्वयं इसका उदाहरण हैं। ऐसे में उन पर भरोसा कौन करेगा?

मोर आवास मोर अभियान के तहत भजपा का प्रदर्शन

■ संसदीय सचिव का घेराव करने पर पुलिस से नोकझोंक

महासमुंद। महासमुंद में आज मोर आवाज मोर अधिकार अभियान के तहत भाजपा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। जिला मुख्यालय के लोहिया चौक मैं सैकड़ों की संख्या में भाजपा की नेता एवं कार्यकर्ता एकत्र हुए और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी, भाषणबाजी के साथ प्रदर्शन किया। भाजपा के इस एकदिवसीय प्रदर्शन में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए।

इस दौरान भाजपाइयों ने आवास योजना, शराब बंदी, कोल खनन, रेत खनन सहित कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को जमकर कोसा। धरना प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता स्थानीय विधायक व संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर के निवास का घेराव करने निकले। विधायक निवास का घेराव करने जा रहे भाजपाइयों को पुलिस ने बस स्टैंड के पास ही रोक लिया।

इस दौरान पुलिस और भाजपाइयों के बीच जमकर झुमाझटकी भी देखने को मिला। इसी दौरान संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर भी अपने घर से बाहर निकल रोड के पास आ पहुंचे। भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने होते हुए एक दूसरे के खिलाफ जमकर घंटों नारेबाजी करते रहे। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ आम जनता को दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी परिपेक्ष में आज महासमुंद में भाजपा ने विधायक निवास के घेराव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिला प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी, पूर्व विधायक पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा शहर और मंडल के अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता धरना व रैली प्रदर्शन में उपस्थित रहे।

संसदीय सचिव ने केंद्र सरकार के खिलाफ साधा निशाना

विधायक निवास घेरने पहुंचे भाजपाईयों का संसदीय सचिव व विधायक विनोद चंद्राकर के अगुवाई में नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग व सभापति बबलू हरपाल, पार्षद राजू चंद्राकर सहित अन्य कांग्रेसियों ने शरबत पिलाकर स्वागत किया। बाद इसके केंद्र में काबिज मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसजनों ने कहा कि, आवास योजना के मामले में विधायक निवास का घेराव करने के बजाय भाजपा नेताओं को दिल्ली जाकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए।

आवास योजना को लेकर भाजपाईयों के विरोध प्रदर्शन पर संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि, भाजपाई इस मामले में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने के लक्ष्य को वापस ले लिया है। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लंबित राशि को जारी नहीं किया जा रहा है, और योजना के लक्ष्य को पूरा नहीं करने का आरोप राज्य सरकार पर ही लगा रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क का हिस्सा नहीं देने के साथ ही जीएसटी में लगातार कटौती कर रही है। माइनिंग रायल्टी की राशि भी नहीं दी ज रही है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आवास योजना के मामले में भाजपा का विरोध महज दिखावेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि, भाजपाईयों को दिल्ली जाकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए।

देवेंद्र यादव के घर चल रही ईडी की कार्रवाई खत्म

■ 18 घंटे तक हुई पूछताछ, समर्थकों ने विधायक को कंधे पर उठाया

दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर-5 स्थित निवास पर चल रही ईडी की कार्रवाई खत्म हो गई। विधायक देवेंद्र यादव से ईडी ने 18 घंटे तक पूछताछ की, जो देर रात तक चली। देर रात 1: 20 बजे सेक्टर 5 विधायक निवास से ईडी की टीम रवाना हो गई। समर्थको की नारेबाजी के बीच ईडी ने पूरी कार्रवाई को लेकर गोपनियता बनाई रखी। कार्रवाई खत्म होने के बाद विधायक के बाहर आते ही समर्थकों ने उन्हें कंधो में उठा लिया।

इससे पहले, जानकारी के मुताबिक सोमवार तड़के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार सदस्यीय टीम ने सीआरपीएफ जवानों के साथ विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर छापा मारा था। बताया जा रहा है कि घर में विधायक की पत्नी डॉक्टर श्रुतिका यादव और माता जी भी मौजूद रहीं। वहीं, ईडी की कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद धीरे-धीरे समर्थकों की भीड़ उनके बंगले के बाहर जमा होने लगी। कार्रवाठ के बीच ही समर्थकों ने निवास के बाहर बैठकर नारेबाजी की, इसबीच सुरक्षाकर्मियों से नोकझोंक भी हुई। यह विरोध प्रदर्शन देर रात तक भी देखने को मिला।

ईडी की सूचना और मदद मांगने के बाद दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव भी कानून-व्यवस्था बनाने मौके पर पहुंचे। भिलाई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को दबाने के लिए केंद्र सरकार ईडी की झूठी कार्रवाई करवा रही है। उसका उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओ का मनोबल तोड़ना है, लेकिन पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ विधायक के साथ खड़ा है।

नकली नोट बाजार में खपाने निकले तीन गिरफ्तार

असली पांच सौ के देते थे पांच हजार, भारी करंसी बरामद

महासमुंद। महासमुंद पुलिस ने नकली नोट खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी पांच सौ रुपये के असली नोट के बदले पांच हजार रुपये देने का लालच देते थे। अभी तक बाजार में लगभग 50 हजार रुपये खपा भी चुके थे। पुलिस ने मुखबिर और गुप्तचरों की मदद से गिरोह के एक नाबालिग बालक समेत तीन अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है।

महासमुन्द जिले में विगत दिनों से सूचना मिल रही थी कि थाना महासमुन्द क्षेत्र में कुछ लोग नकली नोट खपाने व छापने का अवैध कारोबार कर रहे हैं। भीड़-भाड़ वाले स्थानो में नकली नोटो को खपाने का प्रयास कर रहे है। जिसके तहत पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर शेख आरिफ हुसैन के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में सायबर सेल और जिले समस्त थाना और चौकी प्रभारियों को नकली नोट छापने और खपाने वालो का पता तलाश कर कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। जिस पर पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर व गुप्तचर लगाकर गिरोह की तलाश शुरू की। इसी बीच सूचना मिली थी कि नकली नोट छापकर उसे खपाने की फिराक में कुछ लोग बस स्टैंड महासमुन्द यात्री प्रतिक्षालय के आसपास नकली नोट का खपाने के फिराक में घूम रहे है।

सायबर सेल की टीम और थाना सिटी कोतवाली की टीम बस स्टैंड महासमुन्द में घेराबंदी कर इंतजार करने लगी। पुलिस ने मुखबीर द्वारा बताये गये हुलियों से मिलते हुयें तीन लोग बस स्टैंड महासमुन्द में दिखे। जिसे टीम के द्वारा तीन व्यक्ति को घेराबंदी कर दौड़ाकर पकड़ा गया। जिनकी पहचान आपचारी बालक, राम लखन कैवर्त पिता पंचराम कैवर्त उम्र 47 वर्ष, पवन कुमार पिता स्व. सीताराम साहू उम्र 43 वर्ष से हुई। पुलिस की टीम ने जब उन्हें महासमुंद जिलें में आने का कारण पूछा तो वह लोग गोलमोल जवाब देने लगे।

पुलिस की टीम के द्वारा उक्त व्यक्तियों का तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में नगदी रकम मिली। टीम ने जब तीनों आरोपीयों से अलग-अलग गहन पूछताछ की तो तीनों आरोपी टूट गये और आरोपी रामरखन कैवर्त ने बताया कि ओडिशा से पांच लाख रुपये के नकली नोट लेकर आए थे। जो साथी पवन कुमार साहू व अन्य बालक को बांटा गया। पवन कुमार साहू ने लगभग 53 हजार रूपये के नकली नोट को मार्केट में खपा देना बताया। आरोपी बस स्टैंड में आस-पास के लोगों से पांच सौ रुपये के असली नोट के बदले पांच हजार रूपये के नकली नोट खपाने हेतु रखे थे।

आरोपियों के संयुक्त कब्जे से 500-500 रूपये के 888 नग कुल कीमती 444000 रूपये के नकली नोट और तीन विभिन्न कंपनी के मोबाईल कीमती 40000 रुपये जब्त किया। खुलासा करने वालों में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक अशोक वैष्णव, सायबर सेल प्रभारी नसीम उद्दीन खान, विनोद शर्मा, प्रकाश नंद, रवि यादव, डिग्री लाल नंद, हेमंत नायक, संतोष सावरा, संदीप भोई, देव कोसरिया, विकास चन्द्राकर, जितेन्द्र बाघ, रमाकान्त साहू, अभिषेक राजपूत रहे।

घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हाथ जोड़ो यात्रा लेकर पहुंची विधायक

■ भूपेश सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को कराया अवगत

नगरी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओ का वनांचल क्षेत्र के लोगो को अधिक से अधिक लोगो को लाभ दिलाने तथा गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने सिहावा विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव का प्रयास जारी है। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र नगरी के अंतिम छोर में हाथ जोड़ो यात्रा लेकर विधायक डॉ. ध्रुव पहुंची।

ग्राम तुमडीबहार और ठेन्ही में पैदल गांव का भ्रमण किया, सभा लेकर ग्रामीणों को सम्बोधित किया। विधायक को अपने बीच पाकर,ग्रामीण जन काफी खुश हुए। अपनी-अपनी बात रखे और समस्याओं से अवगत कराया। मिडिल स्कूल ठेन्ही में टीचर की मांग मांग पर विधायक ने आस्वासन दिया कि जल्द टीचर की नियुक्ति की जाएगी। ग्रामीण दौड़पडरी पानी की लंबित मांग सामुदायिक भवन निर्माण का भूमिपूजन कार्यक्रम का सम्पन्न हुआ। हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव ने ध्रुव गोड़ समाज परीक्षेत्र तुमड़ीबहार बूढादेव शिवलिंग स्थापना स्थल मे पहुंच कर पूजा पाठ की और क्षेत्र के जनता के लिये सुख समृद्धि की

कामना की, ग्रामीण जनो के द्वारा विधायक का भव्य स्वागत किया गया और भवन निर्माण की मांग रखे। तत्परता से मांग को स्वीकार करते हुये मुख्य अतिथि विधायक डा. लक्ष्मी ध्रुव ने बुढ़ा देव शिव लिंग मंदिर निर्माण के लिये 3 लाख की सौगात दी। समाजिक ग्रामीण जन के द्वारा आभार ब्यक्त किया गया जिसमें प्रमुख रूप से कृपाराम ध्रुव, अश्वनी ध्रुव, सुशील ध्रुव, तरुण ध्रुव, शोभू राम ध्रुव पंचु राम ओटी, लीलाशंकर ध्रुव, केसर बाई, संतोषी बाई, इंदौ बाई शामिल है।

हाथ जोड़ो यात्रा मे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भानेंद्र ठाकुर, भूषण साहू अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेंटी नगरी, राजेन्द्र कुमार सोनी सदस्य कृषि उपज मंडी नगरी, अनवर रजा, जितेंद्र ध्रुव, बलराम ठाकुर, सरपंच सिरधन सोम, राजीव युवा मितान अध्यक्ष, नरेश मांझी,डीके यादव शीतल भंडारी रुपेश नाग ,सदस्य राकेश कश्यप सदस्य रेवस मरकाम, चुम्मन ओटी संतोष ध्रुव महेंद्र मरकाम,सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को भाकपा पदाधिकारियों ने दिया समर्थन

कोरबा। कटघोरा, पाली व पोड़ी उपरोड़ा ब्लाक की 6 परियोजनाओं में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 फरवरी से कटघोरा में आंदोलन कर रही हैं। कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की मांगों को जायज बताते हुए सोमवार को आंदोलन स्थल पहुंचकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव पवन कुमार वर्मा ने समर्थन देने की बात कही। उन्होंने हड़ताली कार्यकर्ता सहायिकाओं को अपने विचारों से आंदोलन पर डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

वर्मा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हो या केंद्र में बैठी सरकार दोनों मजदूर, छात्र, नौजवान, आदिवासी विरोधी हैं। ये सरकारें कारपोरेट के लिए काम कर रही हैं। आम जनता को धर्म जाति मजहब के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हम सब मजदूर वर्ग को एकता के साथ संघर्ष करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार को अपने चुनावी वादे के अनुसार मांगों को पूरा करना चाहिए जो लोग महिलाओं की सुरक्षाए सम्मान व अधिकार की बात करते हैं, वही सबसे ज्यादा आज महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। आज कोई बहन 6500 में कैसे अपने परिवार का जीवनयापन कर सकती हैं। देश में अलग-अलग मानदेय दिया जाता है, तमिलनाडू में सेविका को 20600, मिनी सेविका को 13300, पांडिचेरी में सेविका 19480 मिनी सेविका को 13300, तेलंगाना में सेविका 13650, मिनी सेविका 7800, केरल में सेविका 12000 को मिनी सेविका को 11000, मिलता है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ की मांगों का समर्थन करने पहुंची प्रेमलता

नगरी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन में शामिल हुई पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमलता नागवंशी जहाँ उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका संघ के माँगो को समर्थन दिया। उन्होंने अपने उद्बोधन में भूपेश बघेल सरकार के द्वारा वादाखिलाफी को बताया। कार्यक्रम में उनके साथ नगर पंचायत अध्यक्ष आराधना शुक्ला, महिला मोर्चा प्रदेश सह प्रभारी चेलेश्वरी साहू, जनपद सभापति सुलोचना साहू, मातेश्वरी साहू, कमला साहू, सीता साहू, चंद्रकला साहू, नंदिनी साहू, दमयंती साहू, सुलोचना साहू, खिलेश्वरी साहू, मादरी साहू, साजन साहू, सियाबती ध्रुव, लता बारले, हेमकुमारी सिन्हा, कमला वट्टी, जानकी मंडावी, पनकिन कुंजाम, उमेश्वरी कोसरे, दुर्गा साहू, अनिशा बेगम, पूर्णिमा कौशल व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित हुए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

राम के रास्ते पर चलना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए

नगरी। ग्राम खम्हरिया में शिव बाबा जनकल्याण सेवा समिति के तत्वधान में सम्पन्न हुआ त्री दिवसीय मानस सम्मेलन जहाँ समापन के बेला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँची भाजपा जिला मंत्री व पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमलता नागवंशी। मुख्य अतिथि के रूप में पहुँची प्रेमलता नागवंशी ने अपने उद्बोधन में धर्मांतरण को रोकने पर विशेष ध्यान देने को कहा एवं समाज में टूटते परिवार के विषय में कहा। उन्होंने युवाओं में फैल रहे नशा पान को रोकने को कहा तथा सभी से प्रभु श्री राम जी के रास्ते पे चलने को कहा। उन्होंने गाँव की एकता को बनाए रखने को कहा तथा बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान के केंद्रित करने को कहा। समापन कार्यक्रम अध्यक्षता भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष व भाजपा मंडल प्रभारी रविशंकर दुबे ने किया। उन्होंने रामायण के सार को सीखने पर और जीवन पर अपनाने में जोर दिया।

एनएसयूआई ने किया केंद्र सरकार का पुतला दहन

कोरबा। ईडी के लगातार कांग्रेसी नेताओ के खिलाफ़ कार्यवाही के लेकर युवा कांग्रेस ने कोसाबाड़ी चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या मे युवा कांग्रेसी उपस्थित थे। वह नारे बाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस अवसर पर राजीव युवा मितान के जिला समन्वयक श्याम नारायण सोनी ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से प्रदेश के कांग्रेसी नेताओ पर टार्गेट करके बदनाम वह भयादोहन कर रही है, उससे स्पष्ट होता किए भूपेश बघेल के बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर यह कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है, आने वाले चुनाव मे दोबारा कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए केंद्र की सरकार इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। इस अवसर पर समन्वयक अभय तिवारी ने इस प्रकार की घटना को कायराना बताया और कहा कि मोदी सरकार का चाल चरित्र उजागर होता है। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ईडी के इस प्रकार की कार्यवाही भाजपा की दशा को दर्शाता है।

2 मार्च से भूख हड़ताल पर बैठेंगे भू-विस्थापित

कोरबा। एसईसीएल कुसमुंडा से प्रभावित 12 गांवों के भूविस्थापित रोजगार के पुराने लंबित प्रकरणों पर नौकरी की मांग पर 2 मार्च से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अभी एसईसीएल कुसमुंडा जीएम कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। एसईसीएल प्रबंधन को इससे अवगत कराकर 10 मार्च को खदानबंदी आंदोलन की भी चेतावनी दी है। एसईसीएल कुसमुंडा से प्रभावित ग्राम जरहाजेल, खम्हरिया, मनगांव गेवरा बरपाली दुल्लापुर, बरकुटा, दुरपा, सोनपुरी, जटराज, भैंसमाखार, बरमपुर के भूविस्थापित करीब 25 साल पहले अर्जित भूमि पर रोजगार की मांग कर रहे हैं। सालभर से अधिक समय से एसईसीएल कुसमुंडा मुख्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। भूविस्थापित अब एक बार फिर किसान सभा व भूविस्थापित रोजगार एकता संघ के बैनर तले एसईसीएल प्रबंधन से अपनी मांगे मनवाने जीएम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

कोयला खनन के लिए सर्वे पर महिलाओं ने जताया विरोध

कोरबा। वनमंडल कोरबा के पसरखेत परिक्षेत्र में शामिल कोलगा क्षेत्र के जंगल में कोयला खनन को लेकर सर्वे का काम जारी है। इस बीच सर्वे कर रही टीम कोलगा पहुंची। गांव की महिलाओं को इसकी जानकारी होने पर जंगल आ पहुंची और कोयला खनन को लेकर किए जा रहे सर्वे का विरोध जताया। महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए कंपनी के कर्मचारियों को सर्वे का कार्य छोड़कर वापस आना पड़ा। बताया गया कि दूसरे दिन भी महिलाएं टीम के फिर से पहुंचने की आशंका पर कोलगा के जंगल में डटी रहीं। विरोध कर रही महिलाओं ने सर्वे पर रोक लगाकर कोयला खनन की अनुमति निरस्त करने की मांग की है। राजाडीह कोल ब्लॉक के लिए सर्वे का काम एशियन नामक कंपनी को दी गई है। जो सर्वे के लिए भू-कंपन विधि का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी होल तैयार किए जा रहे थे। जिसका ग्रामीण शुरू से विरोध करते आ रहे हैं।

पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा ने किया धरना-प्रदर्शन

कोरबा। पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने तानसेन चौक कोरबा में धरना प्रदर्शन किया। दोपहर बाद रैली निकाल कर 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन, संचालक लोक शिक्षण पेंशन एवं भविष्य निधि के नाम तहसीलदार सुनील देवांगन को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा के संचालक मनोज चौबे ने सौंपे गए ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आग्रह किया है। चौबे ने बताया कि उनकी मांग सूत्रीय मांगों में पुरानी पेंशन हेतु पूर्व सेवा की गणना किया जाए, पेंशन निर्धारण के लिए केंद्र सरकार की तरह 20 वर्ष किया जाए, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए, जन घोषणा पत्र के अनुसार क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए, पुरानी व नई पेंशन विकल्प चयन के लिए समय सीमा में 3 माह की वृद्धि किया जाना शामिल है। शिक्षक संवर्ग के विभिन्न मांगों को लेकर छग टीचर्स एसोसिएशन, संयुक्त शिक्षक संघ, शालेय शिक्षक संघ के पदाधिकारी व सदस्य धरना में शामिल रहे।

आरटीई के तहत फर्जी तरह से बजट स्वीकृत कराने वाला डीईओ गिरफ्तार

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में वित्तीय वर्ष 2019-20 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह उम्र 62 वर्ष निवासी बीडी महंत उप नगर जांजगीर द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल 172 निजी स्कूलों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र का पुष्टिकरण किया और मांग राशि कुल 57090745 रुपये का भुगतान करने के लिए स्कूलवार जानकारी तैयार की। इसके बाद इसे लोक शिक्षण संचानालय इंद्रावती भवन नया रायपुर को प्रेषित कर अधिक राशि का आहरण कराया गया था। उक्त मामले में मयूरा कान्वेंट स्कूल भी शामिल मिला है। जिसकी जानकारी तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कुंजल सिंह तोमर को भी थी। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है।

दस्तावेजों के आधार पर मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के संचालक राजेन्द्र मौर्य के द्वारा प्रलोभन दिये जाने पर तत्कालीन शिक्षा का अधिकार खंड प्रभारी शिवानंद राठौर, सहायक ग्रेड-2 तथा विकास कुमार साहू, कम्प्यूटर आपरेटर के द्वारा छलपूर्वक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के 2019-20 के मांग पत्रक में अंकित राशि में कांट-छांट, कूटरचना कर पात्रता से अधिक राशि 72,27,690 रुपये का मांग पत्र तैयार किया गया। जिसके बाद स्वीकृति के लिए लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन के कार्यालय संचालक रायपुर को प्रेषित किया गया था।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2019-20 में मयूरा कान्वेन्ट स्कूल बलौदा के खाता में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कुल राशि 72,27,690 रुपये का भुगतान होना पाया गया। जिस पर प्रकरण में अब धारा 467 ,468, 471,120 बढ़ा दी गई है। प्रकरण के आरोपी राजेन्द्र मौर्य, शिवानन्द राठौर एवं विकास कुमार साहू को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। विभाग की जानकारी में प्रकरण आने पर स्वीकृत राशि में से 30 लाख रुपये को आरोपी राजेन्द्र मौर्य के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा के खाते में वापस किया गया।

15 हजार रुपए मयूरा कान्वेन्ट स्कूल के नाम से संचालित खाता में होना और शेष रकम को खर्च करना बताया गया। आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने और उनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने पर राजेन्द्र मौर्य उम्र वर्ष निवासी पीपर मिल के सामने लाल खदान ढेका थाना तोरवा, जिला बिलासपुर, शिवानंद राठौर उम्र 59 वर्ष निवासी निवासी- वार्ड नंबर 19 आई बी रेस्ट हाउस के पिछे जांजगीर और विकास कुमार साहू उम्र 47 वर्ष निवासी-दिप्ती विहार जांजगीर स्थायी पता- ग्राम सरखों पुरेना पारा चौकी नैला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। अब प्रकरण में सम्मिलित आरोपी कुंजल सिंह तोमर उम्र 62 वर्ष निवासी बीडी महंत उपनगर को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

दंतैलों ने मचाई दहशत, एक ही रात में 4 घरों को तोड़ा, अनाज-राशन सब खा गए

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात अभी भी जारी है। बीती रात ग्राम पंचायत कछार में हाथियों ने चार घरों को तोड़ दिया।

वहीं घर में रखे अनाज को भी हाथियों ने खा लिया है। बता दें कि बीते दो महीनों से दो दंतैल हाथियों ने कई दर्जन घरों को तोड़ दिया। हाथियों के दशहत में लोग रतजगा करने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल पत्थलगांव वनपरिक्षेत्र के ग्राम बिलडेगी, चिकनिपानी, सरईटोला, डुमरबहार, वनगांव, लुड़ेग, शेखरपुर, कछार सहित लगभग आधे दर्जन गांवों में हाथियों के आतंक से लोग बेहद परेशान हैं। बीते दो माह में हाथियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वहीं करीब तीन दर्जन से अधिक घरों को तोड़ दिया गया है। घर के लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई है। हाथियों ने घर की बाड़ी में लगी सब्जियों को रौंद दिया। हाथियों के दहशत में ग्रामीण रातभर जागने के लिए मजबूर हैं।

वन परिक्षेत्राधिकारी कृपा सिंधु पैंकरा ने बताया कि वन अमला हाथियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं वन अमला घरों के नुकसान के आंकलन में भी जुटा हुआ है। हाथियों को वहां से खदेड़ने का भी भरसक प्रयास किया जा रहा है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मेघालय में सचिन पायलट ने सरकार बनाने का किया दावा

शिलांग। मेघालय में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक दलों के बीच वार-पलटवार का दौर चल रहा है। कांग्रेस के लिए सचिन पायलट मंगलवार को मेघालय में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा और कहा कि वे आज यहां वादे कर रहे हैं, लेकिन पिछले 8 सालों से केंद्र में और यहां 5 सालों से सत्ता में थे, तो क्या किया है? इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भले ही भाजपा से संसाधनों में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन मतदाताओं और समर्थकों का हमारे साथ हमेशा से आशीर्वाद रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे और अगली सरकार जो बनेगी वह कांग्रेस की होगी। मेघालय के शिलांग में सचिन पायलट ने कहा कि भविष्य के लिए खाली वादों के अलावा वे (भाजपा) क्या पेशकश कर रहे हैं? उन्होंने पूछा कि आपके सहयोगियों को क्या हो गया है कि आप 5 साल से सत्ता साझा कर रहे थे और अचानक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं?

उद्धव गुट की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका पर बुधवार को दोपहर 3.30 बजे सुनवाई होगी। बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 21 फरवरी को जब मामला आया तो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, यदि चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है तो वे चुनाव चिन्ह, बैंक खाते और अन्य अयोग्यताएं अपने हाथ में ले लेंगे। कृपया इसे कल संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), डी वाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, हम इसे कल दोपहर 3:30 बजे सुनेंगे। इसका कारण यह है कि हम सुबह नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि अन्य सहयोगियों को रोका जाए।

संसद में शिवसेना को आवंटित ऑफिस पर शिंदे गुट का कब्जा

नई दिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा शिव सेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को देने के बाद उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल संसद भवन में शिवसेना को आवंटित कार्यालय भी एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया है। लोकसभा सचिवालय ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना कार्यालय आवंटित करने का आदेश दिया है। लोकसभा सचिवालय ने अपने आदेश में कहा है कि संसद भवन का कमरा नंबर 128 शिव सेना संसदीय पार्टी को बतौर कार्यालय आवंटित किया जाता है। इससे पहले एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम, चुनाव चिन्ह और महाराष्ट्र विधानसभा में स्थित पार्टी कार्यालय पर कब्जा मिल चुका है। शिंदे ने कहा कि करीब 76 फीसदी निर्वाचित सदस्य हमें समर्थन दे रहे हैं। हमारे पास नाम और चुनाव चिन्ह भी है। अगर चुनाव आयोग विपक्षी गुट को नाम और चुनाव चिन्ह देने का आदेश देता तो भी वह कोई सवाल नहीं उठाते।

दिल्ली एमसीडी को आज मिल सकता है नया महापौर

नईदिल्ली। दिल्ली नगर निकाय द्वारा महापौर पद पर चुनाव कराने के तीन असफल प्रयासों के पश्चात उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव के लिए मंच तैयार हो गया है और दिल्ली को बुधवार को नया महापौर मिल जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा पिछले सप्ताह निगम सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव 22 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को महापौर, उप महापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते।

भाजपा के खिलाफ एकजुट हुई केसीआर और ओवैसी

हैदराबाद। हैदराबाद स्थानीय निकाय चुनावों में एमएलसी सीट आवंटित करने के एआईएमआईएम के अनुरोध पर विचार करते हुए, बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने एआईएमआईएम का समर्थन करने का फैसला किया है। सीएम ने एआईएमआईएम को सीट आवंटित करने और हैदराबाद स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनावों में उनके उम्मीदवार को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया है। तेलंगाना सीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री केसीआर के समर्थन के एलान के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एमएलसी चुनाव के लिए हमारे उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम राज्य में भाजपा को रोकने के लिए यह रणनीति तैयार की है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा-गोलीबारी, बम धमाकों से त्रस्त था नागालैंड, पूर्वोत्तर से कुछ समय बाद हट सकता है अफस्पा कानून

मोदी के नेतृत्व में भारत शांति के साथ विकास के रास्ते पर बढ़ रहा : शाह

कोहिमा। नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयारी में जुटी हुई है। नागालैंड में भाजपा अपना दमखम लगा रही है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मंगलवार को नागालैंड के तुएनसांग इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागालैंड शांति के साथ विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि मैं आज यहां पर 2014 के पहले के नागालैंड की याद दिलाना चाहता हूं, गोलीबारी, बम धमाको से नागालैंड त्रस्त था। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद शांति समझौता साइन करके नागा शांति वार्ता को आगे बढ़ाया। आज नागालैंड विकास की दिशा में आगे बढ़ा है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले ईएनपीओ ने पूर्वी नगालैंड के लोगों की समस्याओं को उठाते हुए चुनावों के बहिष्कार का आह्वान किया था। हमने ईएनपीओ के साथ चर्चा की है और समझौता अपने अंतिम चरण में है। मैं वादा करता हूं कि चुनाव के बाद पूर्वी नगालैंड के सभी मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नागालैंड की इस धरती पर आप सभी ने मेरा पारंपरिक तरीके से स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं आज नागालैंड के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपनी भाषा को महत्व दीजिए और बच्चों को

अच्छे तरीके से सिखाइए। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने पिछले 9 साल में क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए कई फैसले लिए हैं।

शाह ने कहा कि मोदी के फैसलों की वजह से हिंसक घटनाओं में 70% की कमी आई है, सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने में 60% की कमी आई है, और क्षेत्र को सुरक्षित बनाने वाले नागरिक मौतों में 83% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि हमने जनजातियों के लिए बजटीय आवंटन 2014 में 21,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023 में 86,000 करोड़ रुपये कर दिया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हमने नागालैंड सहित 13 क्षेत्रों में फैली 100 से अधिक विकासात्मक परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया है।

उन्होंने कहा कि नगा शांति समझौते को लेकर बातचीत जारी है और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पहल से उत्तर पूर्व में शांति आ सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस काम की शुरुआत की है, उसका फल जल्द मिलेगा। गृहमंत्री ने ये भी कहा कि वह उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे पूर्वोत्तर भारत से जल्द अफस्पा कानून हटाया जा सकता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लंबे समय से अफस्पा कानून हटाने की मांग की जा रही है और यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। बता दें कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) एक फौजी कानून है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों और सेना को कई विशेष अधिकार मिलते हैं। इनमें बिना वारंट संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी करने और चेतावनी के बाद भी कानून तोड़ने पर आरोपी की मौत तक बल प्रयोग का अधिकार शामिल है। अशांत और उग्रवाद प्रभावित इलाकों में इस कानून को लागू किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बीते कई सालों से यह कानून लागू है। इसे हटाने की मांग पुरानी है। अब अमित शाह के ताजा बयान से पूर्वोत्तर के लोगों की यह मुराद जल्द पूरी हो सकती है।

अमित शाह ने कहा कि पूर्वी नगालैंड में विकास संबंधी कुछ मुद्दे हैं, जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा नगालैंड के बड़े हिस्से से अफस्पा कानून हटा दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले तीन से चार सालों में पूरे उत्तर भारत से अफस्पा कानून को हटा लिया जाएगा। बता दें कि नगालैंड विधानसभा के चुनाव 27 फरवरी को होने हैं। वहीं चुनाव के नतीजे दो मार्च को घोषित किए जाएंगे।

एआईसीसी 'डेलीगेट' सूची पर कांग्रेस सांसद चिदंबरम ने जताई नाखुशी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के 'डेलीगेट' की सूची पर नाखुशी जताते हुए कहा कि जब तक पार्टी ''खास नामांकन'' से दूरी नहीं बनाती, वह हमेशा उन लोगों को पीछे छोड़ देगी जो वास्तव में योग्य हैं।

कार्ति चिदंबरम की यह टिप्पणी उस ट्वीट के जवाब में आई है, जिसमें एआईसीसी डेलीगेट (निर्वाचक मंडल के सदस्य) की सूची में तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख के. टी. लक्ष्मी कंथन को शामिल करने की वकालत की गई थी। कार्ति ने ट्वीट किया, ''जब तक हम ''खास नामांकन'' से दूरी नहीं बनाते, हम वास्तविक रूप से योग्य लोगों को शामिल नहीं कर पाएंगे।'' शिवगंगा से सांसद कार्ति ने एक ट्वीट को रीट्वीट भी किया जिसमें तमिलनाडु से एआईसीसी सदस्यों की सूची में कई पात्र नेताओं के शामिल नहीं होने का जिक्र किया गया था। कांग्रेस ने दिल्ली से जुड़ी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट की सूची जारी कर दी है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के नाम शामिल हैं। इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर का नाम शामिल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। टाइटलर का नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच समिति की रिपोर्ट में शामिल है। दिल्ली से एआईसीसी के कुल 36 निर्वाचित सदस्य और 25 सहयोजित (को-ऑप्टेड) सदस्य हैं। इनमें मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार, वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी और कई अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। टाइटलर के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस का यह कदम दिखाता है कि उसके नेता राहुल गांधी जिन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ''मोहब्बत की दुकान'' की बात की थी, वास्तव में ''नफरत की दुकान'' खोल रहे हैं।

नागालैंड में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए कई बड़े वादे

कोहिमा। नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पारा जबरदस्त तरीके से चढ़ा हुआ है। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नागालैंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नागालैंड में कई बड़े वादे किए और भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से एनडीपीपी, एनपीएफ और बीजेपी ने नागालैंड को लूटा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि लोगों को न्याय मिले और ऐसी सरकार हो जो लोगों के लिए काम करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्वी नागालैंड क्षेत्र के लिए कई उपायों का वादा किया है।

खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद 3000 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन,

शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देगी। साथ ही साथ जॉब कार्ड धारकों को मनरेगा के तहत 100% मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। खड़गे ने आके बताया कि 0% ब्याज पर उच्च शिक्षा के लिए ऋण मिलेगा और स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का इंतजाम करेंगे। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा एक बड़ा घोटाला किया गया था, भाजपा ने स्थिति का लाभ उठाया और सरकार को रातों-रात पलट दिया। उन्होंने कहा कि नागालैंड के लोगों को ठगा महसूस हुआ और सीएम को ब्लैकमेल कर भाजपा ने सरकार बनाई।

2024 में दुरबीन से भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी कांग्रेस

गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि भाजपा-एनडीपीपी सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट के साथ-साथ देश में भी हाशिये पर चली गई है। यह सब राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ है। राहुल गांधी के कांग्रेस की कमान संभालने के बाद से ही पार्टी के नेताओं के व्यवहार में तल्खी आने लगी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल की गई है, जनता इसे देख चुकी है। 2024 में कांग्रेस पार्टी दुरबीन से भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के माध्यम से करेगी।

खेल
प्रमुख समाचार

डेविड वार्नर भारत के खिलाफ अंतिम दो टेस्ट मैच से हुए बाहर

नयी दिल्ली। खराब फॉर्म से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर कोहनी में फ्रेक्चर के कारण मंगलवार को बोर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बाकी बचे दो टेस्ट मैचों से बाहर हो गये जिससे मेहमान टीम को झटका लगा। वार्नर चोट से उबरने के लिए सिडनी जाएंगे लेकिन उनके चार मैच की टेस्ट श्रृंखला के बाद तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए भारत लौटने की उम्मीद है। एकदिवसीय श्रृंखला की शुरुआत 17 मार्च से मुंबई में होगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने एक बयान में कहा, ''डेविड वार्नर भारत के टेस्ट दौरे से बाहर हो गए हैं और स्वदेश लौटेंगे।'' बयान के अनुसार, ''वार्नर को दिल्ली में दूसरे टेस्ट में कोहनी पर चोट लगी थी और उन्हें हेयरलाइन फ्रेक्चर हो गया था। आगे की जांच में पता चला कि उन्हें रिहैबिलिटेशन से गुजरना होगा जिसके कारण वह टेस्ट श्रृंखला के बाकी हिस्से में नहीं खेल पाएंगे।''

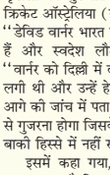

इसमें कहा गया, ''वर्तमान में यह अनुमान लगाया गया है कि वह टेस्ट सीरीज के बाद तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए भारत लौटेंगे।'' ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंद हेलमेट में लगने के बाद कनकशन (सिर में चोट लगने से बेहोशी जैसी स्थिति) की स्थिति के कारण दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में वार्नर की जगह मैथ्यू रेनशॉ ने ली थी। हेलमेट पर गेंद लगने से पहले एक गेंद बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के हाथ में भी लगी थी और उनकी कोहनी में हेयरलाइन फ्रेक्चर हो गया था। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज दो टेस्ट की तीन पारियों में सिर्फ 26 रन बना पाया है। ऑस्ट्रेलिया पहले दोनों टेस्ट गंवाकर चार टेस्ट की श्रृंखला में 0-2 से पीछे है। नयी दिल्ली में वार्नर की जगह ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में पारी का आगाज करने उतरे ट्रेविड हेड के एक मार्च से इंदौर में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में उस्मान ख्वाजा के साथ सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाने की उम्मीद है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

लगातार दूसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में गिरावट

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को हफ्ते के दूसरे दिन भी लाल निशान पर बंद हुआ। उतार-चढ़ाव के बाद बाजार सपाट तरीके से 18 अंक टूटकर 60,672 पर और निफ्टी 18 अंक नीचे 17,826 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में सबसे ज्यादा अदाणी एंटरप्राइसेज के शेयर 3.5% तक फिसले। वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी के शेयर 3.25% बढ़त के साथ बंद हुए। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 311 अंक टूटकर 60,691.54 अंकों के लेवल पर और निफ्टी 97 अंक फिसलकर 17,847.05 अंकों के लेवल पर बंद हुआ था। अमेरिका और यूरोप के वायदा बाजार में आई गिरावट के कारण भारतीय बाजार में भी बिकवाली दिखी। इस दौरान स्पाइसजेट के शेयरों में छह प्रतिशत की गिरावट जबकि एनएमडीसी स्टील के शेयरों में पांच प्रतिशत की उछाल दिखी।

भारत का यूपीआई सिंगापुर के पे-नाऊ से जुड़ा

नई दिल्ली। तेज गति भुगतान और आसान उपयोग की वजह से भारत का यूपीआई दुनियाभर में लोकप्रिय हो रहा है। सिंगापुर के पे-नाऊ और भारत के यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के बीच मंगलवार को सीमा पार कनेक्टिविटी लॉन्च हो गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम हेसिन लूंग इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ के साक्षी बने। इस सुविधा का शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीआई-पेनाऊ लिंकेज (भारत और सिंगापुर के बीच) की शुरुआत दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक उपहार है, जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं इसके लिए भारत और सिंगापुर दोनों के लोगों को बधाई देता हूं।

अदाणी पोर्ट्स समयपूर्व ऋण का करेगा भुगतान

नई दिल्ली। संकटग्रस्त अदाणी समूह की कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन मार्च में परिपक्व होने वाले वाणिज्यिक पत्रों में करीब 1,000 करोड़ रुपये का समय पूर्व भुगतान करने की योजना बना रही है। कंपनी के प्रवक्ता ने सोमवार देर रात एक ईमेल में कहा, यह यह समयपूर्व भुगतान मौजूदा नकदी शेष राशि और व्यावसायिक संचालन से प्राप्त धन से किया जाएगा। सूचना सेवा प्रदाता प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों से पता चलता है कि अदाणी पोर्ट्स के पास मार्च में परिपक्व होने वाले 2,000 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक पत्र हैं। कंपनी की ताजा तिमाही रिपोर्ट के अनुसार बीते 31 दिसंबर तक उसके पास 6,257 करोड़ रुपये नकद रूप में मौजूद थे। बता दें कि कंपनी ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को वाणिज्यिक दस्तावेजों पर 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया है जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को परिपक्व हो गया था।

शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नेक्स्टवेव ने वित्तपोषण दौर में जुटाए 3.3 करोड़ डॉलर

नयी दिल्ली। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नेक्स्टवेव ने मंगलवार को बताया कि निजी इक्विटी कंपनी ग्रेटर पेसिफिक कैपिटल के नेतृत्व में हाल में आयोजित हुए वित्तपोषण दौर में उसने 3.3 करोड़ डॉलर (करीब 272 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। इसमें नेक्स्टवेव की मौजूदा वेंचर निवेशक ओरिओस वेंचर पार्टनर्स भी शामिल हुईं। कंपनी की योजना इस कोष का इस्तेमाल घरेलू और विदेशी बाजारों में उत्पादन और बिक्री बढ़ाने के साथ-साथ अधिग्रहण के लिए करने की है। नेक्स्टवेव के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी राहुल अतुलुरी ने कहा, ''हमारी यात्रा में ग्रेटर पेसिफिक कैपिटल के रूप में नया साझेदार पाने की हमें खुशी है। भारत को प्रौद्योगिकियों का केंद्र बनाने की शुरुआत युवाओं को कुशल बनाने के साथ होगी।

छोटे-मझोले उद्यमों की मदद जरूरी

अजीत रानाडे

वित्तीय मामलों की संसदीय स्थायी समिति, जिसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं, ने बीते अप्रैल में जारी अपनी रिपोर्ट में सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों के महत्व को रेखांकित किया था। हमारे देश में ऐसे उद्यमों की अनुमानित संख्या 6 40 करोड़ है, जिनमें लगभग 99 प्रतिशत बहुत छोटे उद्यम हैं। इनमें पांच से कम लोग कार्यरत हैं तथा इनका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपया भी नहीं है। अर्थव्यवस्था में इनके महत्व को समिति द्वारा रेखांकित इन तथ्यों से समझा जा सकता है- छोटे व मझोले उद्यम का योगदान राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30 प्रतिशत, राष्ट्रीय मैनुफैक्चरिंग उत्पादन में 45 प्रतिशत और निर्यात में 48 प्रतिशत है।

इस क्षेत्र में 11 करोड़ लोग कार्यरत हैं, जो कुल औद्योगिक कामगारों का 42 प्रतिशत हिस्सा हैं। ऐसे आर्थिक महत्व के बावजूद बैंकों या अन्य औपचारिक स्रोतों से दिये जाने वाले कर्ज में इनका शेयर बहुत मामूली है। स्थायी समिति का कहना है कि इन उद्यमों को कर्ज के रूप में 20 से 25 लाख करोड़ रुपये कम मिल रहे हैं। इनकी वित्तीय आवश्यकता अक्सर कामकाजी पूंजी के रूप में होती है क्योंकि छोटे कारोबार मुख्य रूप से वेंडर, सप्लायर और बड़ी कंपनियों (सार्वजनिक और निजी दोनों) के सहायक होते हैं।

छोटे वेंडर और सप्लायर पूरी तरह से अपने ग्राहकों पर निर्भर होते हैं तथा इनमें से कई के पास एक या दो ग्राहक ही हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय रेल के लगभग 10 लाख सप्लायर हैं और उनमें से अधिकतर के लिए रेल ही एकमात्र ग्राहक है। इनमें कुल्हड़, नैपकिन, तौलिया, छोटे पुर्जे या फूड पैकेट आदि के सप्लायर शामिल हैं। यही हाल ज्यादातर सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों का है, जिनके पास ग्राहक के तौर पर एक-दो बड़े कॉरपोरेशन ही हैं। ऐसी व्यवस्था न

के बराबर है, जहां सप्लायरों को कुछ अग्रिम भुगतान हो, जिसे वे कामकाजी पूंजी के रूप में इस्तेमाल कर सकें।

इन उद्यमों से संबंधित कानूनी प्रावधान के अनुसार, जब कोई सेवा या उत्पाद मुहैया कराया जाता है, तो कोई भी ग्राहक वेंडर को भुगतान करने में 45 दिन से अधिक की देरी नहीं कर सकता है। यह संरक्षणात्मक प्रावधान इन उद्यमों के वित्तीय जोखिम के कारण रखा गया है। लेकिन व्यवहार में इसका पालन न के बराबर होता है। छोटे व मझोले उद्यमों के लिए देर से होने वाला भुगतान अभिशाप है।

कानून के मुताबिक 45 दिनों में भुगतान नहीं करने पर कोई कार्रवाई न होने की वजह बिल का ठीक, भरोसेमंद या वैध नहीं होना है। ऐसे में तकनीकी रूप से भुगतान अनिश्चित काल के लिए टाला जा सकता है। एक आकलन के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर देरी से होने वाले भुगतान की राशि 10 लाख करोड़ रुपये तक हो सकती है। मान लें कि अगर यह देरी 12 माह की है, तो ब्याज का खर्च ही एक लाख करोड़ रुपये हो जाता है।

यदि इसका समाधान हो जाए, तो ब्याज की रकम उत्पादक पूंजी में बदल सकती है और इसके लिए सरकार को इन उद्यमों को कोई अनुदान भी नहीं देना होगा। हम यह नहीं चाहते कि भुगतान के लिए बाध्य करने के लिए इंस्पेक्टर राज लाया जाए। इस समस्या को पहले से ही रेखांकित किया जा चुका है। वर्ष 2018 में रिजर्व बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम- स्थापित किया, जिसमें उधार बिल को कुछ छूट पर बेचा जा सकता है।

उदाहरण के लिए, किसी छोटे या मझोले उद्यम का किसी कॉरपोरेशन पर 100 रुपया बकाया है, तो उस बिल को कोई तीसरा पक्ष 97 रुपये में खरीद सकता है और फिर वह कॉरपोरेशन से पूरे 100 रुपये वसूलने की कोशिश करता है। इस व्यवस्था की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बहुत सारे खरीदार (बड़ी कंपनियां) और छोटे-मझोले उद्यम इससे जुड़ें। तभी बिल डिस्काउंटिंग बिजनेस का विस्तार होगा।

अभी इस पहल को सीमित सफलता मिली है क्योंकि कई बड़े कॉरपोरेशन इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ना चाहते। यहां तक कि सार्वजनिक उपक्रम भी हिचक रहे हैं। न तो रिजर्व बैंक और न ही सरकार अनुशासन बहाल कर पा रही हैं। तमिलनाडु में एक नया तरीका अपनाया गया है, जिसमें एक सरकारी पोर्टल पर भुगतान नहीं करने वालों का नाम प्रकाशित किया जाता है। लेकिन इसके लिए उद्यमों द्वारा शिकायत किया जाना जरूरी है।

फिर जेल जाने के काम कर रहे हैं संजय राउत

अजय सेठिया

संजय राउत एक बार फिर जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मनी लांड्रिंग केस में वह सौ दिन जेल में रहे थे। कई बार कोशिशों के बाद विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। वह संजय राउत ही थे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के मन में मुख्यमंत्री बनने की लालसा पैदा करके शिवसेना का भाजपा से चुनाव पूर्व का गठबंधन तुड़वा दिया था। नतीजा यह निकला कि शिवसेना टूट गई, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ रहे थे, तो उन्होंने विभाजन का ठीकरा संजय राउत पर ही फोड़ा था। मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों के दबाव में काम करना पड़ रहा था। शिवसेना विधायकों से उद्धव ठाकरे ने गुलामों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। जिस कारण एकनाथ शिंदे को दो तिहाई विधायक और सांसद तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई।

घमंड में चकनाचूर संजय राउत आए दिन शिंदे को चुनौती देते रहते थे। इसलिए शिंदे ने विभाजन का ठीकरा संजय राउत पर फोड़ा था। उद्धव ठाकरे सिर्फ संजय राउत की सुनते थे, क्योंकि शरद पवार के माध्यम से उन्हें मुख्यमंत्री बनवाने में राउत ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। दो तिहाई विधायकों और सांसदों के समर्थन के बाद तय था कि शिंदे गुट को असली शिवसेना होने की मान्यता मिल जाएगी। चुनाव आयोग ने भले ही देर लगाई, लेकिन अंततः शिंदे गुट को असली शिवसेना होने की मान्यता मिल गई है। जिसपर संजय राउत ने चुनाव आयोग के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा दिए हैं। सवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के खिलाफ उनकी बयानबाजी अब उनके जेल जाने का कारण बनेगी। बड़बोले संजय राउत ने आरोप लगाया है कि शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने के लिए 2000 करोड़ रूपए का सौदा हुआ था। संजय राउत ने यह आरोप बाकायदा ट्विट करके लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का फैसला सौदा है, 2000 करोड़ का यह आंकडा प्रारंभिक है, और यह सौ प्रतिशत सच है। ट्विट के बाद उन्होंने पत्रकारों को यह भी बताया कि सत्तारूढ़ दल के करीबी एक बिल्डर ने उनके साथ यह जानकारी साझा की है। यानि मुख्यमंत्री शिंदे के किसी करीबी बिल्डर ने उन्हें यह जानकारी दी है कि 2000 करोड़ रूपए का सौदा हुआ था।

सुनी सुनाई बात के आधार पर लगाए गए आरोपों से दो बातें स्पष्ट हैं। पहली तो यह कि वह सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। या फिर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके माध्यम से 2000 करोड़ का सौदा हुआ और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग से फैसला करवाया। संजय राउत का दावा है कि वह इस सौदे के सबूत भी पेश करेंगे। शिंदे गुट का यह भी आरोप था कि शरद पवार ने शिवसेना तोड़ने की साजिश के तहत उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाया था। चुनाव आयोग के फैसले के बाद जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह चुरा लिया गया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि महाशक्ति की मदद से शिवसेना का नाम और चुनाव निशान चुरा लिया गया है। तो इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने अपना वही आरोप दोहराया कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी के पास बंधक रख दिया था, जिसे उन्होंने मुक्त करवाया।

नक्सलियों के निशाने पर भाजपा नेता

आशीष कुमार अंशु

छत्तीसगढ़ में भाजपा की नाराजगी का मुख्य कारण उनके नेताओं की एक के बाद एक हो रही हत्या है। एक तरफ भाजपा नेता टार्गेट किलिंग के शिकार हो रहे हैं फिर भी राज्य सरकार इन हत्याओं के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार पर आरोप है कि उसने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। भाजपा नेताओं की नृशंस हत्या के मामले में किसी अधिकारी को सस्पेंड तक नहीं किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। अब तक सरकार ने कोई जांच नहीं बिठाई लेकिन अब राज्य सरकार विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की बात कर रही है।

छत्तीसगढ में कहा जा रहा है कि नक्सली जानबूझकर भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं। नक्सलियों द्वारा टार्गेट कीलिंग का जो सिलसिला बस्तर में प्रारंभ हुआ उसके पहले शिकार भाजपा नेता पूर्व सरपंच बुधराम करताम किलेपाल थे। उनका शव 16 जनवरी को घर से दो किमी दूर सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला।

करताम जगदलपुर में भाजपा के जिलामंत्री थे। भाजपा के अनुसार उनकी हत्या एक राजनीतिक षडयंत्र है, जिसे नक्सलियों ने अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार, उनकी मृत्यु एक दुर्घटना थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव के सिर पर चोट के निशान थे। सड़क पर उनके जूते पड़े मिले। उससे आधा किमी दूरी पर उनका शव था। यह सब देखकर हत्या की आशंका जताई गई थी। जिसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया।

अभी छत्तीसगढ़ भाजपा अपने नेता बुधराम करताम के शोक से बाहर भी नहीं आई थी कि पांच फरवरी को बस्तर अन्तर्गत बीजापुर जिले के उसूर मंडल अध्यक्ष नीलकंठ कक्केम की हत्या नक्सलियों ने कर दी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी नक्सलियों ने कक्केम को अल्टीमेटम दिया था लेकिन 05 फरवरी को अपनी साली के शादी समारोह में शामिल होने वे आवापल्ली थाना क्षेत्र के अपने पैतृक गांव पेंकरम आये तो मौके पर ही पहुंचकर नक्सलियों ने परिवार के सामने चाकू और कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बस्तर प्रवास के एक दिन पूर्व 10 फरवरी की रात आठ बजे नक्सलियों ने नारायणपुर जिले के छोटेडोंगर में जिला भाजपा उपाध्यक्ष सागर साहू को उनके घर में घुसकर गोली मार दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारायणपुर (बस्तर) पहुंचकर 13 फरवरी को सागर साहू को श्रद्धांजलि दी। साहू के परिजनों से मुलाकात कर विश्वास दिलाया कि पीड़ित परिवार के साथ पूरी बीजेपी खड़ी है। इस दौरान उन्होंने सागर साहू के पार्थिव शव पर बीजेपी का झंडा ओढ़ाया।

नड्डा ने बस्तर प्रवास के दौरान जनसभा में भी कार्यकर्ताओं की हो रही टारगेट कीलिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के शहीद वीर सिपाहियों के परिजनों से कहूंगा कि आपका बेटा इस लड़ाई में अकेला नहीं है, पूरी 18 करोड़ सदस्यों की पार्टी आपके साथ खड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद नक्सली हमले बढ़े हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बस्तर से लौटते ही नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के हितामेटा गांव के पूर्व सरपंच व भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रामधर अलामी की हत्या कर दी। अलामी 10 फरवरी को कुछ काम से तुलथूली गांव गए थे। दूसरे दिन शनिवार, 11 फरवरी को वे जब अपने गांव लौट रहे थे, तब नक्सलियों ने कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर दी। आदिवासी बहुल बस्तर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। सभी सीटों पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा बस्तर पर फोकस कर रही है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि नक्सली जिस तरह से भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, इससे भाजपा कमजोर होगी, जिसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा नेताओं की नृशंस हत्या करने वाले नक्सली कहीं %गोदी नक्सली% तो नहीं हैं? भाजपा नेताओं की हत्या के पीछे कांग्रेस की शह होने की बात इसलिए भी स्थानीय चर्चा का विषय है क्योंकि बीजेपी नेताओं की सुरक्षा राज्य सरकार ने वापस ले ली है। बस्तर के बीजेपी नेता केदार कश्यप ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं की निशानदेही करके हत्या की जा रही है, दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भाजपा नेताओं की सुरक्षा भी हटा ली है।

झीरम कांड के सबूत पर विवाद

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा टारगेट कीलिंग की बात होने पर झीरम घाटी में कांग्रेसी नेताओं के नरसंहार की बात आ ही जाती है। दस साल पुरानी बात है। वह भी विधानसभा चुनाव का साल था। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। 200 लोगों के काफिले पर नक्सलियों ने अचानक हमला बोला था। 30 लोगों की जान गई थी, जिसमें कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। हमले के मुख्य टारगेट बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा थे। सलवा जुडूम का नेतृत्व करने की वजह से नक्सली उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। नक्सलियों ने उनके शरीर पर करीब 100 गोलियां दागीं और चाकू से 50 से ज्यादा वार किए। हत्या के बाद नक्सलियों ने उनके शव पर चढ़कर डांस भी किया था।

यह बात उल्लेखनीय है कि भाजपा सलवा जुडूम के समर्थन में खड़ी थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने झीरम कांड पर कहा कि, %%चुनाव से पहले भूपेश बघेल कह रहे थे, मैं झीरम कांड का सबूत जेब में लेकर घूम रहा हूं। जब सरकार बनेगी तो सबूत दिखाऊंगा। तो अब वे मुख्यमंत्री हैं। जेब से सबूत निकालकर दिखाएं। झीरम कांड के एक प्रत्यक्षदर्शी कवासी लखमा भूपेश सरकार में मंत्री हैं।

बहरहाल, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर नक्सली जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए यह चुनौती है कि वे कैसे इस जिन्न से निपटते हैं। नक्सलियों द्वारा की जा रही भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग प्रदेश सरकार के काम काज पर गंभीर सवाल उठा रही है।

प्रसंग — सच्ची उपासना

एक बार गुरु नानक सुल्तानपुर पहुँचे। वहाँ उनके प्रति लोगों की श्रद्धा देख यहाँ के काजी को ईर्ष्या हुई। उसने सूबेदार दौलतखाँ के खूब कान भरे और शिकायत की कि यह कोई पाखण्डी है, इसीलिए आज तक नमाज पढ़ने कभी नहीं आया। सूबेदार ने नानकदेव को बुलावा भेजा, किन्तु उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। जब सिपाही दुबारा बुलाने आया, तो वे उसके पास गये। उन्हें देखते ही सूबेदार ने डाँटते हुए पूछा, पहली बार बुलाने पर क्यों नहीं आये ? मैं खुदा का बन्दा है, तुम्हारा नहीं नानकदेव ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया। अच्छा! तो तुम खुद को खुदा का बन्दा भी कहते हो। मगर क्या तुम्हें यह मालूम है कि किसी व्यक्ति से मिलने पर पहले उसे सलाम किया जाता है ? मैं खुदा के अलावा और किसी को सलाम नहीं करता । तब फिर खुदा के बन्दे ! मेरे साथ नमाज पढ़ने चल क्रोधित हो सुबेदार बोला। और नानकदेव उसके साथ मस्जिद गये। सूबेदार और काजी तो नीचे बैठकर नमाज पढ़ने लगे, मगर गुरु नानक वैसे ही खड़े रहे। नमाज पढ़ते-पढ़ते काजी सोचने लगा कि आखिर उसने इस दम्भी (नानकदेव) को झुका ही दिया, जबकि सूबेदार का ध्यान घर की ओर लगा हुआ था। बात यह थी कि उस दिन अरब का एक व्यापारी बढ़िया घोड़े लेकर उसके पास आनेवाला था। वह सोचने लगा कि शायद व्यापारी उसका इन्तजार करता होगा, इसलिए नमाज जल्दी खत्म हो, तो वह घर जाकर सौदा तय करे। नमाज खत्म होने पर वे दोनों जब उठ खड़े हुए, तो उन्होंने नानकदेव को चुपचाप खड़े पाया। सूबेदार को गुस्सा आया। बोला, तुम सचमुच ढोंगी हो। खुदा का नाम लेते हो, मगर नमाज नहीं पढ़ते।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1998 1998 शीतकालीन ओलंपिक जापान में नागानो में आयोजित किया गया।
1998 18 वें शीतकालीन ओलंपिक खेल जापान के नागानो में बंद हुए।
2006 कम से कम छह पुरुषों ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी नकदी डकैती का मंचन किया, जो कि केंट के टोनब्रिज में एक सिक्यूरिटीज डिपो से बैंक नोटों में ् 53,116,760 चोरी कर रहा था।
2010 ग्रीस और यूरोपीय संघ द्वारा ग्रीस के लिए 20 - 25 बिलियन यूरो की वित्तीय सहायता योजना की योजना बनायी गयी।
2011 न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में रिक्टर पैमाने पर 6.3 की तीव्रता वाले भूकंप से 181 लोगों की मौत हुई।
2011 लिबियन तानाशाह मुअम्मर अल-गद्दाफी टेलीविजन पर दिखाई देता है और क्रांति के प्रमुख बने रहने का दावा करता है।
2011 न्यूज़ीलैंड में 6.5 एमएलए के भूकंप के झटके के बाद न्यूजीलैंड को अपनी सबसे खराब आपदाओं में से एक का सामना करना पड़ा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

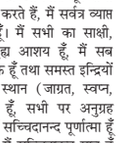

ब्रह्मविद्योपनिषद (भाग-05)

गतांक से आगे...

मैं आदि, मध्य एवं अन्त से विहीन हूँ। मैं आकाश के समान हूँ। मैं आत्म चैतन्य रूप हूँ तथा आनन्द चेतन घन के सदृश हूँ। मैं आनन्द रूप, अमृत स्वरूप हूँ, मैं आत्म-संस्थित हूँ, अन्तर (सभी की अन्तरात्मा) भी मैं ही हूँ। (मैं) आत्मकाम हूँ तथा आकाश से (अधिक व्यापक) परमात्मा स्वरूप परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं केवल हूँ, कवि हूँ, कर्माध्यक्ष हूँ। मैं ही कारणों का कारण अर्थात् अधिपति हूँ, मैं गुप्त आशय हूँ, रखने वाला हूँ एवं मैं ही नेत्रों का भी नेत्र हूँ। मैं चिदानन्द हूँ, चेतना प्रदान करने वाला हूँ, चिद्घन एवं चिन्मय स्वरूप हूँ। मैं ज्योतिर्मय हूँ और ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिरूप मैं ही हूँ। मैं अन्धकार में साक्ष्य स्वरूप हूँ, तुर्य का भी तुर्य हूँ, अन्धकार से परे हूँ, मैं दिव्य देवस्वरूप हूँ, दुर्दर्श और दृष्टि का आधार ध्रुव (शाश्वत) हूँ ।

मैं निर्विकार (विकार रहित), नित्यपूत (सदैव पवित्र), निर्गुण, निस्पृह हूँ में इन्द्रियों से रहित नियन्ता, निरपेक्ष एवं निष्कल (कलारहित) हूँ । मैं परमात्म पुरुष हूँ,परम पुराण हूँ। मैं परावर (ज्ञानसमुद्र) हूँ, प्राज्ञ-प्रपञ्च का शमन करने वाला भी हूँ। मैं परामृत तथा पुरातन पूर्ण प्रभु हूँ। मैं पूर्णानन्द, एक बोध रूप हूँ तथा प्रत्यग् (अन्तरात्मा) एवं एक- रस (सर्वदा एक रूप) भी मैं ही हूँ।

मैं बुद्धि हूँ, मैं ही भूतपाल अर्थात् समस्त प्राणियों का गलन करने वाला हूँ, प्रकाश स्वरूप भगवान् भी मैं हूँ । महादेव, महाज्ञेय एवं महान् महेश्वर भी मैं ही हूँ। मैं विमुक्त हूँ, विभु हूँ, वरण करने योग्य हूँ तथा मैं ही व्यापक हूँ। मैं श्रेष्ठ वैश्वानर एवं वासुदेव हूँ तथा सम्पूर्ण विश्व का चक्षु रूप भी मैं ही हूँ। मैं विश्व से अधिक हूँ, मैं विश्व का कर्त्ता विशद विष्णु हूँ, मैं शुद्ध, शुक्र, शान्त स्वरूप हूँ, शाश्वत तथा शिव भी मैं हूँ। मैं समस्त भूत प्राणियों का अन्तरात्मा हूँ, मैं नित्य एवं सनातन हूँ। मैं अपनी महिमा में स्थित रहकर सदैव प्रकाशित होता रहता हूँ। मैं सभी के अन्तःकरण में स्वयं ज्योति रूप में स्थित एवं समस्त प्राणियों का अधिपति हूँ। सभी भूत-प्राणी मुझमें ही निवास करते हैं, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ तथा सभी का सम्राट् हूँ। मैं सभी का साक्षी, सर्वात्मा, सब भूतों का गुह्य आशय हूँ, मैं सब इन्द्रियों के गुणों का प्रकाशक हूँ तथा समस्त इन्द्रियों से रहित भी हूँ। मैं तीन स्थान (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति) से अतीत (परे) हूँ, सभी पर अनुग्रह अनुकम्पा करने वाला हूँ। मैं सच्चिदानन्द पूर्णात्मा हूँ तथा सभी का प्रेमास्पद हूँ। मैं सच्चिदानन्द मात्र हूँ एवं स्वयं प्रकाशमान चेतन घनस्वरूप हूँ। मैं सत्य स्वरूप, सन्मात्र (सत्यस्वरूप), सिद्ध तथा सभी की आत्मा हूँ।समस्त (प्राणियों का आधार स्वरूप, सत्य स्वरूप, सभी के बन्धन को हरने (काटने वाला, सबको अपना ग्रास बनाने वाला, सभी को देखने वाला और सभी का अनुभव रूप मैं ही हूँ।

भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे रामकृष्ण परमहंस

ललित गर्ग

प्राचीनकाल से ही भारत की रत्नगर्भा वसुंधरा माटी में ऐसे कई संत और महान व्यक्ति हुए है जिन्हें उनके कर्म, ज्ञान और महानता के लिए आज भी याद किया जाता है। जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से न सिर्फ स्वयं को प्रतिष्ठित किया वरन् उनके अवतरण से समग्र विश्व मानवता धन्य हुई है। इसी संतपुरुषों, गुरुओं एवं महामनीषियों की श्रृंखला में एक महापुरुष हैं रामकृष्ण परमहंस। वे एक महान संत, शक्ति साधक तथा समाज सुधारक थे। इन्होंने अपना सारा जीवन निःस्वार्थभाव से मानव सेवा के लिये व्यतीत किया, इनके विचारों का न केवल कोलकाता बल्कि समूचे राष्ट्र के बुद्धिजीवियों पर गहरा सकारात्मक असर पड़ा तथा वे सभी इन्हीं की राह पर चल पड़े।

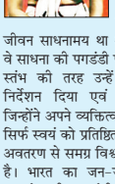

रामकृष्ण परमहंस युग के साथ बहे नहीं, युग को अपने बहाव के साथ ले चले। उनका जीवन साधनामय था और जन-जन को वे साधना की पगडंडी पर ले चले, प्रकाश स्तंभ की तरह उन्हें जीवन पथ का निर्देशन दिया एवं प्रेरणास्रोत बने। जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से न सिर्फ स्वयं को प्रतिष्ठित किया वरन् उनके अवतरण से समग्र विश्व मानवता धन्य हुई है। भारत का जन-जन श्री रामकृष्ण परमहंस की परमहंसी साधना का साक्षी है, उनकी गहन तपस्या के परमाणुओं से अभिषिक्त है यहां की माटी और धन्य है यहां की हवाएं जो इस भक्ति और साधना के शिखरपुरुष के योग से आप्लावित है। संसार के पूर्णत्व को जो महापुरुष प्राप्त हुए हैं, उन इने-गिने व्यक्तियों में वे एक थे। उनका जीवन ज्ञानयोग, कर्मयोग एवं भक्तियोग का समन्वय था। उन्होंने हर इंसान को भाग्य की रेखाएं स्वयं निर्मित करने की जागृत प्रेरणा दी। स्वयं की अनन्त शक्तियों पर भरोसा और आस्था जागृत की। अध्यात्म और संस्कृति के वे प्रतीकपुरुष हैं। जिन्होंने एक नया जीवन-दर्शन दिया, जीने की कला सिखलाई।

रामकृष्ण परमहंस भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में प्रमुख हैं। उनको दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और यही वजह है कि उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग अपनाया और कठोर साधना की। वह मानवता के पुजारी थे और उनका दृष्टान्त था कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग-

ऑपरेशन दोस्त : मानवता और कूटनीति की विजय

सरस चंद्र त्रिपाठी

तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चला रही एनडीआरएफ की टीम शुक्रवार को स्वदेश लौट आयी। एनडीआरएफ जवानों का पहला सी-17 ग्लोबमास्टर विमान सुबह 9ः00 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। इस टीम ने दस दिनों तक 6 फरवरी को तुर्की में आये भीषण भूकंप के बाद लोगों की मदद की थी।

भारत और तुर्की के कूटनीतिक संबंधों को सामान्य या अच्छा नहीं कहा जा सकता किंतु 6 फरवरी को आये भूकंप के बाद भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के सनातन मूल्यों के अनुरूप बचाव और सहायता कार्य के लिए तत्काल प्रस्ताव कर दिया। भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी तैयारी तत्काल शुरू कर दी। भारत उन पहले देशों में था जिसने तुर्की को न सिर्फ सहायता का प्रस्ताव किया बल्कि सबसे पहले बचाव और राहत दल भेजा।

दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में से एक सी-17 ग्लोबमास्टर में हर प्रकार की दवाएं, राहत सामग्री, भोजन सामग्री; यहां तक की जेसीबी, चिकित्सा वाहन तथा सेना और एनडीआरएफ का 90 विशेषज्ञों का दल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आपरेशन दोस्त के लिए रवाना हुआ । सबसे दुर्भाग्य का विषय यह था कि इस दुख की घड़ी में तुर्की का सबसे अच्छा दोस्त समझे जाने वाले पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के इस जहाज को, जो कि राहत और बचाव सामग्री लेकर जा रहा था, अपने वायु मार्ग से जाने की अनुमति नहीं दी। इससे राहत सामग्री और बचाव दल के पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ लेकिन ईरान के रास्ते होते हुए इस विमान को तुर्की पहुंचाया गया।

भारत की त्वरित प्रतिक्रिया ने कुछ असंतुष्ट स्वरों को जन्म दिया है। एक राय यह है कि भारत के प्रति तुर्की के कोल्ड (ठंडे) दृष्टिकोण के कारण तुर्की इस तरह की उदारता और सदाशयता का पात्र नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान किसी भी परिस्थिति में भारत के परोपकार के योग्य नहीं है। एक ही सांस में तुर्की और पाकिस्तान का उल्लेख करना, भारत के प्रति एक कूटनीतिक भ्रम होगा। भू-राजनीति में, देशों को एक स्पेक्ट्रम पर व्यवस्थित किया जाता है और मित्रता और निकटता की डिग्री को वर्गीकृत किया जाता है।

पाकिस्तान और तुर्की बिल्कुल अलग हैं और इन देशों में मानवीय संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के मानदंड अलग होने चाहिए। वैसे भी संपूर्ण विश्व को एक ही परमपिता की संतान मानने वाले भारत ने कभी धर्म, भाषा, रंग या विचारधारा के कारण भेदभाव नहीं किया। हांलांकि तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की छवि एक कट्टरपंथी इस्लामिस्ट की है। उन्होंने भारत का कश्मीर ही नहीं सीएए के मामले में भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर विरोध किया। किन्तु भारत ने सदाशयता का परिचय देते हुए राजनीति पर कूटनीति और धर्म पर मानवता को वरीयता दी। यही हमारे देश और संस्कृति का बड़प्पन है।

भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता और अत्यधिक प्रभावशाली जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। तुर्की को भारत की अंतरराष्ट्रीय हैसियत का अनुमान है। आर्थिक पक्ष देखें तो भी बैलेंस आफ पेमेंट भारत के पक्ष में है। भारत और तुर्की के मध्य लगभग 7.975 बिलियन डॉलर का व्यापार है। इसमें से लगभग 30ल आयात और 70ल निर्यात है। तुर्की की मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर पहुंच गई है और तुर्की भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भारत विरोध इन परिस्थितियों में अंकारा की मदद नहीं करेगा, एर्दोगन यह जानते हैं। कूटनीतिक पैंतरेबाज़ी के बावजूद, दुनिया के किसी भी हिस्से में मानवीय संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया एक ठोस नैतिक संहिता द्वारा निर्देशित रही है। संकट के समय मानवीय सहायता प्रदान करना और सताए गए लोगों को शरण देना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमारे सहिष्णुता और उदारता के इतिहास के अनुकूल है।

दुनिया के मात्र दो देश हैं जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पर समर्थन किया; वे हैं तुर्की और मलेशिया। जब से रिसेप तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने खुलेआम प्रो-पाकिस्तान और एंटी-इंडिया पॉलिसी लागू की है। वस्तुतः उनके नेतृत्व में तुर्की एक कट्टरपंथी देश बनता जा रहा है। पुष्ट समाचार यह भी है कि तुर्की आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित संगठनों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहा है। तुर्की ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की कठोर भर्त्सना भी की है और यह आरोप भी लगाया कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है।

किंतु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीनतम परंपरा वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का अनुगमन करते हुए शत्रु और मित्र देश का भाव मिटाकर मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए तुर्की को तत्काल राहत और बचाव कार्य के लिए प्रस्ताव किया। भारत की बचाव राहत टीम, जिसमें भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) सम्मिलित है, ने जो कार्य तुर्की में किया उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा पूरी दुनिया के अनेक देशों ने ही नहीं बल्कि तुर्की के नागरिकों ने भी की। तुर्की जैसे देश को संकट की घड़ी में सहायता देकर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ एक कूटनीतिक विजय पाई है वरन भारतीय मानव मूल्यों को पुनर्स्थापित करते हुए संसार को यह बताया है कि हमारी संस्कृति देश, रंग, भौगोलिक भेदभाव को नहीं मानती और मानवीय मूल्यों में विश्वास करती है। भारत के कार्यों ने तुर्की की सरकार और वहां के नागरिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत के विषय में वह अपना दृष्टिकोण बदले। जिन्हें वे अपना मित्र देश समझते थे उसने तुर्की की कठिनाइयों में फंसी जनता के लिए राहत सामग्री भी अपने वायु मार्ग से जाने की अनुमति नहीं दी। स्वयं पाकिस्तान कोई भी सहायता करने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां एक लीटर पेट्रोल 300 में बिक रहा है। लोगों के पास खाने के लिए चावल और आटा नहीं है। सबसे अधिक अपमानजनक बात यह है कि पाकिस्तान ने जो थोड़ी बहुत राहत सामग्री तुर्की को भेजी थी वह वही राहत सामग्री थी जो तुर्की ने पाकिस्तान को उसके यहां सिंध में आई बाढ़ के समय भेजी थी। तुर्की की सरकार ने इसे स्वयं मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। पाकिस्तान में भी इसकी बहुत अधिक चर्चा है और जो लोग स्वतंत्र विचारक हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऐसे कुकृत्य की बहुत आलोचना की है।

एक तरफ भारत की सदाशयता और दूसरी तरफ पाकिस्तान का यह धोखा तुर्की के लोगों और तुर्की की सरकार में अवश्य विचार पैदा करेगा कि असल में मित्र और शत्रु कौन है। कहा जाता है कि कठिन वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो आपका वही असली मित्र होता है। इस परिभाषा पर भारत बिल्कुल खरा उतरा है।

दूसरी तरफ भारत ने नाटो देशों से भी अधिक जल्दी और अधिक सहायता प्रदान करके यह प्रमाणित कर दिया है कि वह आवश्यकता पड़ने पर कितनी तेजी से काम कर सकता है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इस विपत्ति के समय तुर्की की आर्थिक सहायता करके अपनी आर्थिक शक्ति का भी परिचय दे रहा है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने तुर्की की सहायता करके एक कूटनीतिक विजय, राजनैतिक दूरदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की शक्ति को मानवता के मापदण्डों के साथ स्थापित कर दिया है।

गांधी आज

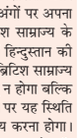

अंग्रेज़ों के साथ संबंध

ब्रिटिश राज्य के साथ हिन्दुस्तान का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए इसके निश्चय का अधिकार हिन्दुस्तान की जनता को है। जबतक यह अधिकार न हो, स्वराज्य मिल गया यह नहीं कह सकते। इस अधिकार सहित ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हिन्दुस्तान का संबंध बना रहे तो इससे पूर्ण स्वराज्य में न्यूनता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उस स्थिति में हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य के साथ समान अधिकार भोगता रहेगा, अर्थात् अपनी विशालता और महत्ता के अनुपात में वह साम्राज्य के दूसरे अंगों पर अपना प्रभाव डालता रहेगा। हिन्दुस्तान और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच अगर ऐसा संबंध हो जाय और उसमें हिन्दुस्तान की नीति सत्य और अहिंसा की पोषक रहे, तो ब्रिटिश साम्राज्य आज की भांति जगत् के लिए भय की वस्तु न होगा बल्कि सब राष्ट्रों को अभय देनेवाला हो सकता है। पर यह स्थिति आने के पहले हिन्दुस्तान को लंबा रास्ता तय करना होगा। उसे अपनी शक्ति और संस्कृति को पहचान कर, उसके प्रति वफादार रहकर, उस विषय की अपनी साधना पूरी करनी होगी। जबतक वह निर्बलता और कायरता का सहारा लेता है तबतक यह असंभव है। ब्रिटिश साम्राज्य आसुरी व्यवस्था है और उसका नाश होना ही चाहिए, यह ठीक है। पर ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश जाति एक चीज नहीं है। ब्रिटिश जाति में जगत् की अथवा यूरोप की दूसरी जातियों से अधिक दोष या कम गुण नहीं हैं। इस जाति में अनेक आदरणीय और अनुकरणीय सद्गुण हैं और यदि आज के विषम संबंध के कारण हम उनकी कद्र न कर सकें तो इसे दुर्भाग्य ही समझना होगा। स्वराज्य- भारत में रहनेवाले अंग्रेज़ दूसरी अल्पसंख्यक जातियों- समुदायों की तरह रह सकते हैं। वे हिन्दुस्तान की दूसरी जातियों की भांति हिन्दुस्तानी बनकर देश की सेवा में अपना भाग अर्पण कर सकते हैं और पिछले प्रकरण में बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार देश की दूसरी जातियों के साथ उनका संबंध रहेगा। पर यदि वे परदेशी बनकर ही रहना पसंद करें तो हिन्दुस्तान के हित के अनुकूल शर्तों पर ही वे हिन्दुस्तान की नौकरी कर सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

उईके ने रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की

रायपुर। राज्यपाल सह कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के डिपार्टमेन्ट ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉ. केशरी लाल वर्मा के 1 अप्रैल 2023 को पूर्ण हो रहे कार्यकाल के उपरांत कार्यभार करने की ग्रहण करने की तिथि से प्रोफेसर शुक्ला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का नये कुलपति होंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा 14 फरवरी 2023 को उक्त आशय का आदेश जारी किया गया है। वही छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) के धारा 17 के उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एमिटी विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति प्रोफेसर डॉ. पीयूष कांत पांडे को एमिटी विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। इस सम्बद्ध में आज राजभवन सचिवालय से आदेश जारी किया गया है।

भारत-पाकिस्तान संबंध पेचीदगियों से भरा: कर्नल सुनील मिश्रा

रायपुर। भारत और पाकिस्तान के मध्य का संबंध इतिहास, भूगोल और वैचारिक मतभेद ही अब तक निर्धारित करते आए हैं। कश्मीर से लेकर सर क्रीक तक, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अपने घरेलू मंच तक, पाकिस्तानी नेतृत्व का भारत विरोधी मानसिकता ही दोनों देशों के संबंध को रसातल में डाला हुआ है। यह विचार भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कर्नल सुनील मिश्रा ने साइंस कॉलेज, रायपुर के रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार में संबोधित करते हुए कहा है। कर्नल मिश्रा के अनुसार पाकिस्तान की दिनोंदिन बिगड़ती आर्थिक हालत; उनके कमजोर नेतृत्व तथा गलत नीतियों को परिलक्षित कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के मध्य अभी वार्तालाप में डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान जब तक अपने नीतियों पर पुनर्विचार नहीं करेगा और आतंकी गतिविधियों को समर्थन करने से तौबा नहीं करेगा, तब तक ना तो उसकी आर्थिक हालत सुधरने वाली है, ना ही पाकिस्तान का भारत से संबंध मधुर होने वाला है। आज के इस सेमिनार की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ पी सी चौबे ने किया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ पी सी चौबे, विभागाध्यक्ष डॉ गिरीश कांत पांडेय, डॉ प्रवीण कड़वे ने अपने विचार रखे। इस सेमिनार में डॉ गीतांजलि चंद्राकर, शशांक शुक्ला सहित बड़ी संख्या में शोधार्थी एवं छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम हेतु धन्यवाद ज्ञापन मालविका नायर ने ज्ञापित किया तथा कार्यक्रम का संचालन मनीष पटेल ने किया।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने कराना होगा भूमि सत्यापन

बिलासपुर। केन्द्र शासन द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत पात्र किसानों के बैंक खाते में सालाना 6 हजार रूपए की राशि तीन किस्तो में दो-दो हजार रू राशि दी जा रही है। योजना का लाभ केवल पात्र कृषकों को मिले इस हेतु किसानों को अपने पारित कृषि भूमि का सत्यापन (लैंड सिडिंग) कराना, अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में लिंक कराना व ईकेवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर ने सभी बैंकों को किसानों के बैंक खाता में आधार लिंक करने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही पोस्ट आफिस में भी खाता खोलने पर पोस्ट बैंक द्वारा आधार सिंडिंग का कार्य किया जा रहा है। उक्त तीनों कार्य पूर्ण करने के उपरांत ही पात्र कृषकों के बैंक खाते में अगली किस्त हस्तांतरित होगी। उप संचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि बिलासपुर जिले के 12689 कृषको द्वारा अभी तक अपने बैंक खाते में आधार लिंक नहीं कराया गया है। यदि आपके द्वारा अपने बैंक खाते में आधार नम्बर लिंक नहीं कराया गया है तो बैंक शाखा में जाकर आधार नम्बर लिंक करावें।

जवानों की शहादत पर राजनीति, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए आरोप

राजनांदगांव। बोरतालाब के पास नक्सलियों ने घात लगाकर जो जवानों पर हमला कर दिया था.जिसमें दोनों की मौत हो गई.इस शहादत के बाद चारों तरफ नक्सलियों के खिलाफ गुस्सा पनपा है.वहीं इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस सरकार पर जवानों की शहादत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है. नारायण चंदेल का कांग्रेस पर आरोप नेता प्रतिपक्ष नारायण चन्देल ने कहा कि सोमवार छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के पास नक्सलाइट मूवमेंट में हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं. हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं .लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रदेश कांग्रेस के किसी नेता ने, क्या मंत्री ने और ना ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने अपने प्रेसवार्ता में इन जवानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता व्यक्त नहीं की. नारायण चंदेल ने आगे कहा कि यह इस बात का स्पष्ट सबूत है कांग्रेस कितनी संवेदनहीन हो गई है.

कांग्रेस महाधिवेशन से पहले आक्रामक हुई भाजपा

चुनाव तक स्थिति बराबरी पर करने की कोशिश

रायपुर। पिछले कुछ दिनों से भाजपा लगातार एक के बाद एक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रही है. अब तक भाजपा सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर सरकार और कांग्रेस को घेरती रही है. लेकिन अचानक से अब भाजपा के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरते नजर आ रहे हैं. इसमें चाहे प्रदेश में बढ़ते अपराध का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो या फिर पीएम आवास ना मिलने का मामला हो. ऐसे तमाम विषयों को लेकर भाजपा लगातार आक्रामक हो गई है. इतना ही नहीं जैसे-जैसे महाधिवेशन के दिन नजदीक आ रहे हैं. भाजपा का सरकार और कांग्रेस पर आक्रमण तेज हो गया है.

कई मुद्दों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे

सोमवार को भी भाजपा के द्वारा पीएम आवास ना मिलने के मामले को लेकर प्रदेश के 11 कांग्रेसी विधायकों का घेराव किया. इस तरह के प्रदर्शन भाजपा की ओर से लगातार जारी है. पीएम आवास को लेकर विधानसभा स्तर पर मोर आवास मोर अधिकार के नाम से भाजपा के द्वारा प्रदर्शन किया गया. रायपुर में भी कांग्रेसी विधायकों का भाजपा ने प्रदर्शन कर घेराव किया. इस बीच गृह मंत्री के बंगले का भी घेराव कर भाजपाइयों ने जोरदार नारेबाजी की.भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर का विरोध- इतना ही नहीं कुछ दिन पहले भी नक्सलियों के द्वारा भाजपा नेताओं की हत्या के मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर भाजपा में काफी आक्रोश था.

आपमें है ताकत, तो हमारे खिलाफ भी लिखो एफआईआर

इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत का कहना है कि नक्सलियों के द्वारा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या के बाद जब भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम किया गया. उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है. मैं सरकार से आग्रह करता हूं और चुनौती देता हूं, भाजपा का कार्यकर्ता ना दबने वाला है, ना झुकने वाला है. हमारे कार्यकर्ता को दबंगता के साथ दबाने की कोशिश करोगे, तो पार्टी कार्यकर्ता प्रखरता और मुखरता के साथ सड़कों पर आएंगे. हमने भी चक्का जाम किया है, हम भी उसमें शामिल थे, आपमें ताकत है, तो हमारे खिलाफ भी एफआईआर लिखो. भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं.

भाजपा अघोषित मोर्चा प्रकोष्ठ ईडी, सीबीआई आईटी के माध्यम से हो रही है सक्रिय

कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि जैसे जैसे अधिवेशन नजदीक आ रहा है, भाजपा सक्रीय हो रही है. लेकिन वह अपने कार्यकर्ताओं के दम पर सक्रिय नहीं हो रही है, अपने जो अघोषित मोर्चा प्रकोष्ठ हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनके माध्यम से सक्रिय हो रही है. भाजपा जब राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती है, तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है. दरअसल भाजपा कायर और भेदू पार्टी है. उसके अंदर में राजनीतिक क्षमता नहीं है, जो हमारा राजनीतिक तौर पर मुकाबला कर सके.

कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि निश्चित तौर पर यदि भाजपा के पास नेता और कार्यकर्ता होते, उनमें साहस नहीं है कि मुद्दों के आधार पर बात करें. हम बेनकाब करेंगे अपने अधिवेशन में. विभिन्न विषयों पर जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे, तो न सिर्फ इस देश की जनता की आंखें खुलेंगी, दुनिया के जनता की आंखें खुलेगी. भाजपा इसी से डरी हुई है, बौखलाई हुई है. इसलिए उन्होंने ईडी को आगे किया है. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हमारा अधिवेशन ईडी की कार्रवाई के बाद और ज्यादा मजबूत तरीके से होने वाला है.

हमने कार्यकर्ताओं रोके रखा, नहीं तो दफ्तर से बाहर नहीं आ सकते ईडी अधिकारी

इस दौरान कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह तो हमने रोका है, नहीं तो ईडी के अधिकारी अपने दफ्तर बाहर नहीं निकल पाते. हमारा कार्यकर्ता इतना ज्यादा आक्रोशित है. हमारे वरिष्ठ नेताओं ने रोक रखा हुआ है. अन्यथा यहां पर बहुत ज्यादा अप्रिय स्थिति बनने वाली थी.

अग्रेसिव मोड में है भाजपा, चुनाव तक हो सकती है बराबर की स्थिति

वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा कहना है कि मैं ऐसा नहीं मानता कि अभी महाधिवेशन के दौरान भाजपा अग्रेसिव मोड में है. भाजपा 5 महीने पहले से ही अग्रेसिव में चली गई है. जिस तरीके से उनके अध्यक्ष आ रहे हैं, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं, जिस तरह उनके प्रभारी बदले हैं, उनकी जो तमाम अग्रेसिव मूड की टीम है, उनका छत्तीसगढ़ प्रवास हो रहा. इससे कह सकते कि भाजपा अग्रेसिव मूड में तो है और चुनाव आते आते इस चुनाव को 50-50 में लेकर आ जाएगी.चुनाव तक स्थिति बराबरी पर ला सकती है भाजपा- वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा कहना है कि जिस तरीके से आरएसएस का शिविर लग रहे हैं. बस्तर में उन्होंने फोकस किया है. कोरबा में गृहमंत्री आए, बस्तर में नड्डा आए, उनके शिविर भी बस्तर पर फोकस करने के लिए लगा है. तमाम वह प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करते रहेंगे और आने वाला वक्त जो यह चुनाव एक तरफा था, उसे बराबर पर लाकर खड़ा कर देंगे.

कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक आयोजित किया गया है. जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे।

आरडीए अध्यक्ष ने गृह मंत्री से की कमल विहार में पुलिस थाना खोलने की मांग

रायपुर। कमल विहार योजना में पुलिस थाना खोलने की मांग को लेकर रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने कल प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से उनके निवास में मुलाकात की। श्री धुप्पड़ ने गृह मंत्री को बताया कि पिछले काफी समय से कमल विहार योजना क्षेत्र के नागरिक यह शिकायत कर रहे हैं कि वहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है तथा काफी चोरियां और लूट हो रही है।

सड़कों के किनारे बनी सीवर लाईन के ढक्कन, उद्यानों में लगी ग्रिल काट कर चोरी की जा रही है। इससे वहां कमल विहार के निवासियों में काफी रोष व भय व्याप्त है। वहां के निवासियों और प्रतिनिधि मंडलों ने प्राधिकरण कार्यालय में आकर उनसे कई बार मुलाकात कर पुलिस थाना शुरु करवाने का अनुरोध किया है। धुप्पड़ ने गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपते हुए चर्चा के दौरान यह बताया कि कमल विहार योजना काफी बड़ी आवासीय योजना है जो लगभग 16 सौ एकड़ क्षेत्र में विकसित की गई है। प्राधिकरण ने इस योजना में पुलिस थाना निर्माण के लिए सेक्टर - 9 में 8206 वर्गफुट के भूखंड का प्रावधान किया हुआ है। वर्तमान में कमल विहार में लगभग 1950 भूखंडों में मकानों का निर्माण कर आवंटित निवास कर रहे। वहां 100 मकानों का निर्माण भी आवंटितियों व्दारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सेक्टरों में प्राधिकरण व्दारा 5800 ईडब्लूएस और एलआईजी फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण होने को है जिसका शीघ्र ही कब्जा दिया जाएगा। कमल विहार की बसाहट में लगातार वृध्दि हो रही है इसीलिए योजना क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से शीघ्र ही पुलिस थाना खोला जाना चाहिए। गृह मंत्री तामध्वज साहू ने इस पर आरडीए अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही प्रशासनिक तौर पर ठोस कार्रवाई कर कमल विहार योजना में पुलिस थाना की स्थापना करेगें। आरडीए अध्यक्ष ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ को भी एक पत्र सौंपा है।

कस्टम मिलिंग के लिए 102 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की कृशल प्रबंधन के कारण अब तक कस्टम मिलिंग के लिए 102 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है, जबकि लगभग 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ जारी कर दिया गया है। किसानों से समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की सफलतापूर्वक खरीदी की गई है। गौरतबल है कि मुख्यमंत्री की पहल पर पिछले वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए सीधे उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव शुरू किया गया था, जिसके चलते राज्य सरकार को परिवहन व्यय में काफी कमी आयी है। इसके साथ ही धान खरीदी के बाद धान उठाव की लंबी प्रक्रिया से भी निजात मिली है।

छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है वाय 20 समिट का आयोजन

- एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और 27 महाविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम

रायपुर। भारत, वर्ष 2023 में जी 20 की अध्यक्षता कर रहा है. जिसके तहत भारत में जी 20 के मुख्य आयोजन के इतर विभिन्न अन्य सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है. इन्ही आयोजनों के तहत वाय 20 समिट का भी आयोजन किया जा रहा है. भारत की जी-20 की अध्यक्षता 'अमृतकाल' के प्रारंभ का भी प्रतीक है. अमृतकाल 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू हुआ है. जो 25 साल की अवधि यानी स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष तक मनाया जाएगा.

वाय 20, जी 20 के तहत एक ऑफिसियल यंग ग्रुप है, जो जी 20 देशों के युवाओं को एक बेहतर प्लेटफार्म प्रदान करता है. इस यूथ 20 इंगेजमेंट ग्रुप में भारत का मुख्य फोकस जी 20 सहित विश्व के युवा लीडरों को एक मंच प्रदान करना है, जहाँ से वह अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके. इस आयोजन के तहत पॉलिसी रिकमेन्डेशन को वाय 20 शिखर सम्मेलन में सार्वजनिक रूप घोषित किया जाता है. साथ ही इसे जी 20 समिट के दौरान वर्ल्ड लीडर के सामने प्रस्तुत किया जाता है. अगले 8 महीनों के दौरान भारत में मुख्य वाय 20 समिट इंडिया से पहले, देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों में युवाओं से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे साथ ही यूथ-20 से सम्बंधित पांच विषयों पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे.

भारत की अध्यक्षता के दौरान वाय-20 की एक्टिविटी ग्लोबल यूथ लीडरशिप और साझेदारी पर केंद्रित होंगी.वाय 20 समिट का मुख्य उद्देश्य विश्वस्तर पर यूथ इंगेजमेंट को बढ़ावा देना है. इस मंच से जी20 देशों के यूथ सहित भारत द्वारा आमंत्रित गेस्ट कंट्री के यूथ भी अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर सकेंगे. ऐसे कार्यक्रमों के योजना से यूथ जनरेशन में लीडरशिप का विकास होगा, जो उन्हें आगे चलकर अपने देश या किसी बड़े संगठन के नेतृत्व के लिए तैयार करेंगे.इसी श्रृंखला के तहत छत्तीसगढ़ के चुनिंदा 27 महाविद्यालयों और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 16 से 25 फरवरी, 2023 विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

खदान प्रभावित ढपढप और कसरेंगा में पेयजल संकट

- किसान सभा ने दी 6 मार्च को कार्यालय घेराव की चेतावनी

कोरबा। ढेलवाडीह कोयला खदान से प्रभावित गांव ढपढप और कसरेंगा में पेयजल संकट गहरा गया है। इसका समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में आज कोरबा महाप्रबंधक के नाम ढेलवाडीह सब एरिया प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया और दोनों गांवों में पाईप लाईन के माध्यम से घर-घर पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने, तालाबों में खदान का पानी भरने, बिगड़े बोरवेल पंपों को सुधारने, खनन से कुंओं और घरों को पहुंचे नुकसान के कारण प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा देने तथा ढपढप सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण कराने की मांग की गई।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से किसान सभा नेता जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा, सुभद्रा, बुधवारो बाई, मत कुंवर, सुनीला, मंगली बाई, शांति बाई, रामायण बाई, कृष्णा बाई, अधीना, राजमती, टिकैतिन, सुमेन्द्र सिंह कंवर, दामोदर श्याम, नरेंद्र यादव आदि शामिल थे। समाधान नहीं होने पर किसान सभा ने 6 मार्च को सब एरिया कार्यालय ढेलवाडीह का घेराव करने की चेतावनी भी दी है।

उल्लेखनीय है कि कोयला के अंधाधुंध और अनियोजित खनन के कारण ढपढप और कसरेंगा में जल स्तर काफी नीचे चला गया है और सभी कुंएं, तालाब व बोरवेल सुख गए हैं। कई घरों में दरारें पड़ गई है। किसान सभा नेता प्रशांत झा और जवाहर सिंह कंवर ने आरोप लगाया है कि एसईसीएल प्रबंधन इस क्षेत्र से केवल मुनाफा बटोर रहा है और उसे पेयजल व निस्तारी जैसी आम जनता की बुनियादी सुविधाओं से कोई लेना-देना नहीं है।

किसान सभा के नेता और ढपढप पंचायत के पंच नरेंद्र यादव और कंवल सिंह बिंझवार ने बताया कि प्रबंधन को कई बार समस्या से अवगत कराया गया है। वहीं राजमती और रामायण बाई ने कहा कि एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पिछले साल खाना पूर्ति के नाम पर टैंकर चलाया गया था, जो नियमित नहीं आता था और सभी ग्रामीणों को पानी नहीं मिलता था। जो पानी दिया जाता था, वह पानी पीने योग्य भी नहीं रहता था। किसान सभा नेताओं ने कहा है कि गांव में पानी की आपूर्ति के साथ सभी मांगो पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती, तो 6 मार्च को कार्यालय में तालाबंदी करते हुए घेराव किया जाएगा।

मंत्री रविन्द्र चौबे के बंगले के घेराव आज

रायपुर। मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में जिला भाजपा ने अध्यक्ष जयंती भाई पटेल के नेतृत्व में रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों में पहले नुक्कड़ सभाएँ की एवं स्टॉल लगाकर वंचित हितग्रहियों से फॉर्म भरवाए एवं उनकी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने आक्रामक मोड में है मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे हे भूपेश सरकार के नारों के साथ रायपुर शहर जिला की 3 विधानसभाओं जहाँ काँग्रेस विधायक है का घेराव किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने डॉ. खूबचंद बघेल को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नदृष्टा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कृषक नेता स्वर्गीय डॉ. खूबचंद बघेल की 22 फरवरी को पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन किया है। मुख्यमंत्री ने डॉ. खूबचंद बघेल को अपने विनम्र श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा है कि डॉ. खूबचंद बघेल ने अपना पूरा जीवन समाज और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, सहकारिता के क्षेत्र सहित कई सामाजिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूबचंद जी ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्ष में डॉ. खूबचंद बघेल का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की व्यवस्था मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी स्मृति में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए डॉ. खूबचंद बघेल सम्मान स्थापित किया है। वही विस् अध्यक्ष डॉ महंत ने कहा कि डॉ. बघेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे, वे अपनी शासकीय सेवा से त्यागपत्र देकर 1930 में गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गये।

मोर आवास-मोर अधिकार अभियान में भाजपा ने खोला मोर्चा

भूपेश बघेल सरकार नहीं चाहती कि गरीबों को पक्की छत नसीब हो - नितिन नबीन

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी अभियान मोर आवास-मोर अधिकार के तहत आज 10 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा नेताओं ने जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार से संघर्ष करने और वंचितों को आवास दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर आवासहीन को पक्का मकान दे रहे हैं लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार इसमें बाधक बन रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास मिले लेकिन यह सरकार बाधा बन रही है। भाजपा की सरकार बनने पर हर गरीब को उसका प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। भाजपा इस गरीब विरोधी सरकार को विवश करने विधानसभा का घेराव करेगी।

आज मोर आवास-मोर अधिकार अभियान के तहत कवर्धा, खरसिया, कटघोरा, बिल्हा,

संजारी बालोद, नवागढ़, भानूप्रतापपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा में आवासहीनों से तथ्यों की जानकारी ली गई। भाजपा भूपेश बघेल सरकार की अड़ंगेबाजी के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित गरीब जनता के बीच पहुंच चुकी है। भाजपा राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास वंचितों के बीच जा रही हैं और जनता की आवाज बुलंद कर रही है।

प्रदेश भाजपा सह प्रभारी नितिन नबीन ने कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में मोर आवास-मोर अधिकार अभियान के तहत आवास वंचितों से भेंट की और उन्हें प्रधानमंत्री आवास दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि हमारी केन्द्र सरकार ने देश के सभी गरीबों को पक्का मकान देने का कार्य हाथ में लिया है लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार नहीं चाहती कि यहां के हमारे गरीब भाई-बहनों को पक्की छत नसीब हो। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार और उसके मंत्री केंद्र सरकार की योजनाओं को निगल जा रहे हैं।लेकिन भाजपा सरकार आते ही हम इन्हे सजा दिलवाएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को उसका अधिकार दिलवाएंगे।

राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडेय ने कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में मोर आवास- मोर अधिकार अभियान के तहत आवास वंचितों के साथ घेराव कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारी माताओं-बहनों को सम्मान दिलाने के लिए पूरे देश में शौचालय की व्यवस्था की। पूरे देश में गरीबों को पक्का मकान दे रहे हैं ताकि हमारी माताएं, बहनें ,बेटियां बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान में रह सकें लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां पक्के आवास में रहें इसलिए वह बाधाएं उत्पन्न कर रही है। यह सरकार महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में अभियान का नेतृत्व करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबों के आवास पर डाका डाल रही है। उनका आवास छीन रही है। यह सरकार नहीं चाहती कि गरीब पक्के मकान में रहे। जिससे छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। भाजपा राज्य के आवासहीनों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है।

प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र में अभियान के दौरान क्षेत्रीय विधायक राज्य के कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल के निवास का घेराव कार्यक्रम का नेतृत्व किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबों को आवास से वंचित करने का काम कर रही है।

ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन

प्रदर्शन मे बड़ी संख्या मे कांग्रेसी जुटे, भाजपा सरकारी संस्थाओ का दुरूपयोग कर रही है

रायपुर। कांग्रेस के नेताओ पर ईडी के छापेमारी के विरोध मे रायपुर के कांग्रेसी सड़क पर उतर आये। आज जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण एवं शहर कांग्रेस कमेटी रायपुर के तत्वाधान मे ईडी कार्यालय का घेराव प्रदर्शन हुवा कांग्रेस जन रैली के रूप मे पहुंचकर कार्यालय के सामने पहुंच गये वही पर पुलिस एवं कांग्रेस जनो के बिच धंक्का मुक्की हुई,कांग्रेस जन जम कर मोदी के खिलाफ,भाजपा के खिलाफ नारे लगाते आफिस के सामने धरने पर बैठकर नारे लगाते रहे। केंद्र की भाजपा सरकार सभी मामलों मे विफल रही चाहे वह किसान की आय दुगुनी की बात हो,महगाई कम करने की बात,युवाओ को रोजगार नही दे पाई एवं अडानी द्वारा एसबीआई एवं एलआईसी में किये गये घोटालो को छिपाने व लोगो का घ्यान भटकाने हेतु विपक्षी दलो पर ईडी, सीबीआई, आईटी, का दुरूपयोग कर रही है।जिसका आज धरना प्रदर्शन कर घेराव कर विरोध किया। इसलिए वे ईडी को सामने ला रहे है।

शहर प्रवक्ता मोहम्मद मजीद फहीम ने बताया कि मंगलवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पर कांग्रेसजनो ने ईडी दफ्तर का हंगामेदार घेराव किया। ईडी दफ्तर का घेराव करने बड़ी संख्या मे कांग्रेस जन पुजारी काम्प्लेक्स पचपेडी नाका के पास एकत्र हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ईडी दफ्तर पहुचे। ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस ने बैरिकेट लगा रखे थे। पुलिस बल तैनात थे। ईडी कार्यालय जाने से मना करने पर कांग्रेस जन वही जमीन पर धरने पर बैठ गये। वहां केंद्र सरकार के विरोध मे जमकर नारे लगे। मीडिया से चर्चा करते हुए वरिष्ठ विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि कांग्रेस के होने वाले महाधिवेशन मे भाजपा बाधा डालने का प्रयास कर रही है। भाजपा द्वारा कायराना हरकत की जा रही है। सत्ता और शासन का उपयोग कर डराना चाहती है। हम डरनेवाले नही हमारा अधिवेशन सफल होकर रहेगा। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि महाधिवेशन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास को हम सफल नही होने देंगे। हमारे नेता भूपेश बघेल एवं मोहन मरकाम के मार्ग दर्शन मे महाधिवेशन सफल होगा। नरेंद्र मोदी के पास लड़ने के लिए कोई भाजपा के कार्यकर्ता नही है।

अडानी का नाम अब परिवहन घोटाले से जुड़ा, महापौर ने दर्ज करायी शिकायत

सोमवार को जिस प्रकार ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई रायपुर से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हुई कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तगड़ा विरोध किया है। इस बीच रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने नया खुलासा किया है,उन्होने कोयला परिवहन घोटाले में अडानी समूह के शामिल होने की लिखित में शिकायत पुलिस से करते हुए एसआईटी जांच की मांग की है। इस मामले में तमाम तथ्यों और गवाहों के बयान के बाद भी केंद्र सरकार और ईडी अडानी समूह पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अपनी शिकायत में ढेबर ने कहा है कि ईडी की ओर से पंजीबद्ध मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है अथवा जिन लोगों से गवाही ली गई है, उन्होंने इसके बारे में लोगों को बताया है। उनके मुताबिक -रायगढ़ स्थित जीपी-3 कोयला खदान में सूर्यकांत तिवारी और जोगिंदर सिंह की कंपनी जय अंबे ट्रांसपोर्ट कंपनी अडानी के लिए काम करती थी। अडानी समूह के कर्मचारी कोयला परिवहन का 70 रुपया प्रति टन नकद लेते थे। यह काम सूर्यकांत तिवारी देखता था। वह अडानी समूह के लिए 2010 से काम कर रहा है। इस संबंध में जानकारी के बावजूद ईडी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। वह इन तथ्यों को छिपा रही है।

विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में निमंत्रण

प्रो. के पी यादव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा , विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में संस्थान खोलने देने के फैसले ने शैक्षिक बहस का मुद्दा बना दिया है । कई शिक्षाविद इसका स्वागत करने में डर रहें हैं। कंही ये एक नई समस्या न बन जाय। एक तरफ भारत अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को संभाल के तरक्की के रस्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विदेशी विश्वविद्यालयों से हमारी अपेक्षाएं कितना पूरी होंगी ये सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। भारत में वर्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान देने वाले एक हजार से अधिक विश्वविद्यालय एवं बयालीस हजार से अधिक कॉलेजों से पास होने वाले लाखों छात्रों को रोजगार का संकट रहता है, दलील यह दी जाती है की ये छात्र कौशलों में निपुण नहीं होते, इनकी शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी नहीं उतर रही।

कमियों को खोजना एवं उनको दूर किये जाने का प्रयास सतत जरूर किया जाना चाहिए। ये कह देना की यंहा के संस्थान काबिल छात्र देने में नाकाम हैं, ये गलत होगा। इस विशाल देश में हर साल लाखों छात्र ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एवं पीएचडी डिग्री लेकर अपना भविष्य खोजने में लग जाते हैं, जनसँख्या के अनुसार सभी को नौकरी मिलना आसान नहीं रहता, फिर भी अधिकांश छात्र / छात्राएं कुछ न कुछ रोजगार तो कर ही लेते है। ये भी दलील दी जा रही हैं की निजी विश्वविद्यालयों की मंहगी शिक्षा समाज के केवल 5 से 10 प्रतिशत छात्रों को ही मिल पा रही है, अब इसी कड़ी में ये विदेशी विश्विद्यालय भी जुड़ जायेंगे, जिसमे शिक्षा प्राप्त करना सब के बस की बात नहीं होगी। कैम्ब्रिज, ऑक्सफ़ोर्ड, बोस्टन, हॉवर्ड जैसे विश्विद्यालय में दाखिले के लिए छात्रों को बहुत अधिक फीस चुकानी पड़ेगी, क्योंकि डॉलर और रुपये का फर्क भी फीस जमा करने में बाधा डालेगा ।

जंहा हम शिक्षा जगत में विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे है, वहां किसी दूसरे देश की फिलॉसोफी पर चल रहे विश्वविद्यालयों पर कितना भरोसा किया जा सकता है , यह विचारणीय प्रश्न हो सकता हैं , जिसका उत्तर भविष्य में छिपा हैं। भारत की अपनी एक गौरवशाली पृष्ठभूमि रही है। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति प्राचीनकाल से आगे बढ़ते जा रही है। कितने आक्रमणकारी आये और वापस गए। मुग़लों ने सैकड़ों साल राज किया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया किन्तु हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा में उतना चोट नहीं आयी, जितना अभी विदेशी विश्वविद्यालयों के आने पर समाज में एक डर का माहौल बन रहा है। इन विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकलने वाले छात्र क्या हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को आगे लेकर जा पाएंगे या फिर फेमा कानून का पालन करते हुए भारतीय रुपये को डॉलर, यूरो, पाउण्ड में मुनाफा कमाकर ये विश्विद्यालय अपने देश ले जायेंगे। निजी विश्वविद्यालयों में काम करने वालों के लिए चुनौतीपूर्ण समय आ सकता है।

क्या ये विश्विद्यालय भारत जैसे विशाल देश में शिक्षा को सर्व सुलभ करा पाएंगे ? यदि नहीं, तो फिर क्यों नहीं हम अपने संसाधनो एवं शिक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करने के बजाय इनकी शरण में जा रहे, यदि ऐसा हुआ तो भारतीय विश्वविद्यालयों की भूमिका क्या होगी ? क्या उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जायेगा ? तर्क यह दिया जा रहा हैं, कि आने वाले सालों में विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का खर्च अरबों डॉलर बचाया जा सकता है, जो काफी हद तक सही प्रतीत होता है। यह तर्क भी दिया जाता है, कि भारतीय विश्वविद्यालय विदेशियों से प्रतियोगिता करके अपना स्तर सुधार सकेंगे।

यह देश बहुत विविधताओं से भरा है, यही इसकी खूबसूरती और यही इसकी मजबूती का कारण भी है, कि सैकड़ों साल गुलाम रहने और शिक्षा, संस्कृति पर चोट होने के बाद भी आज हम तीव्रगामी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, किन्तु प्रश्न यही है, कि हम कितनी तेजी से हमारी विरासतों, संस्कृतियों को संजोते हुए आगे बढ़ सकते हैं, कंही यह नया प्रयोग हमें इधर कुँआ, उधर खांई वाली स्थिति में ना ले जाये। अपनी जरूरतों एवं संसाधनों के अनुसार कार्य करना ठीक रहता है, किसी और के भरोसे जिम्मेदारियों को सौपना या हिस्सेदारी देना शायद जल्दबाजी में किया गया निर्णय न साबित हो। वैसे भी नए प्रयोगों से बचने वाले कुछ नया और बेहतर कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न शिक्षा विदों एवं वाइस चांसलर से सुझाव मांगे गए हैं । उपरोक्त क्रम में भारत सरकार का यह कदम सराहनीय प्रतीत होता हैं । सरकारी एवं प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थानो को एक प्रतिस्पर्धा का माहौल मिलेगा एवं जो छात्र / छात्राएं विदेशों में जाकर मंहगी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें भी काफी विराम लगेगा। क्योंकि उपरोक्त विश्व रैंक 500 तक वाले विदेशी संस्थानों को ही भारत में आमंत्रित किया जा रहा हैं छात्रों का बहार / विदेश में आने-जाने तथा रहने का खर्च बचेगा। साथ ही उपरोक्त अध्धयन हेतु जो पैसा विदेशों में चला जाता था, उस पर भी विराम लगेगा।

बेरोजगारी भत्ते के लिए तरह तरह की शर्ते प्रदेश के युवाओं के साथ षड्यंत्र-अमित

रायपुर। बेरोजगारी भत्ते की घोषणा पर भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी के कहा प्रदेश की धोखेबाज और युवा विरोधी सरकार ने फिर से एक बार युवाओं को छलने का काम किया है टी एस सिंहदेव जी ने राहुल गांधी जी को सार्वजनिक रूप से यह बताया था कि बेरोजगारी भत्ता 10 लाख लोगों को प्रतिमाह 2500 रु दिया जाएगा जिसका सालाना बजट 3 हजार करोड़ होगा ,अब जब 4 साल बाद घोषणा हुई है तो सालाना बजट 450 करोड़ रुपए बताया गया हैं। अमित ने कहा तरह-तरह की शर्तें डालकर युवाओं के साथ अन्याय किया गया है जो 12वीं पास नहीं है उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, जिसने दो साल पहले पंजीयन नहीं कराया उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा ,जिसके पिता सरकारी या निजी नौकरी में है, उसे भत्ता नहीं मिलेगा, यह सब युवाओं के साथ एक षड्यंत्र है चुनावी वर्ष में भी युवाओं के साथ कांग्रेस ने अपना धोखा बरकरार रखा है और सरकार अपने वादे से मुकर गई है इसका स्पष्ट प्रमाण सरकार ने स्वयं दे दिया है।

वादा नहीं फिर भी भत्ता देने का फैसला-कांग्रेस

भूपेश मंत्रीमंडल द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारो को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी नीति का परिणाम है कि आज आधा प्रतिशत से भी कम बेरोजगारी दर होने के बावजूद युवाओं को कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। यह भूपेश है तो भरोसा है के नारे का मूर्त रूप है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिना वायदा किये भी राज्य के युवाओं की आवश्यकताओं को महसूस कर बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र के अतिरिक्त जनता को राहत देने राज्य में समृद्धि लाने के लिये अनेक योजनाओं को चलाया है, निर्णय लिया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना चलाया गया जिससे प्रदेश के आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार हुआ।

राज्यपाल उइके को दी विदाई

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को आज यहां माना स्थित स्टेट हैंगर पर भावभीनी विदाई दी गई। उन्हें विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुश्री उइके को पुष्प गुच्छ भेंट कर विदाई दी। इसके साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, कोरबा की सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायकी बृजमोहन अग्रवाल ने भी सुश्री उइके को विदाई दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, रायपुर संभाग के आयुक्त यशवंत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो, अजय यादव, कलेक्टर रायपुर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

जल जीवन मिशन में किसके संरक्षण में हो रहा गोलमाल-पटेल

रायपुर। पीएचई दफ्तर से जल जीवन मिशन से सम्बंधित अहम दस्तावेज की फाइलें और कम्प्यूटर से डाटा गायब होने के बावजूद दो साल से तत्कालीन प्रमुख अभियंता पर कोई सख्त कार्रवाई न होने पर भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने सवाल किया है कि आम जनता से सीधे जुड़े केंद्र सरकार के इस महत्वपूर्ण मिशन में किसके संरक्षण में गोलमाल हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार को छुपाने की गरज से की गई दस्तावेजों की चोरी पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। पटेल ने कहा कि अपने चार नेताओं की टारगेट किलिंग पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक रोज में एफआईआर दर्ज कराने वाली भूपेश बघेल सरकार को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से इतना ज्यादा प्रेम है कि जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार के बावजूद सरकार सो रही है। जबकि इस गंभीर मामले में फौरन कार्रवाई की जरूरत थी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस का इकलौता काम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना और उनसे उगाही करना है। यह सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचने नहीं दे रही। हद हो गई कि जनता के जीवन के बेहद अहम अंग पानी तक को कांग्रेस सरकार के पाले हुए भ्रष्ट अफसर पी गए।

ईडी के छापे कुंठा, हताशा एवं मानसिक दरिद्रता का प्रतीक - रिजवी

रायपुर। मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने प्रदेश में कांग्रेस के विशाल राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले भाजपा द्वारा कांग्रेसियों पर करवाए जा रहे ईडी के छापों को भाजपाई कुंठा, हताशा एवं मानसिक दरिद्रता का प्रतीक निरूपित करते हुए कहा है कि यह सब कुछ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन द्वारा किए जा रहे विकास के कार्य भाजपाईयों के गले नहीं उतर रहे है तथा कांग्रेसियों को हतोत्साहित करने की यह नाकाम कार्यवाही है। इस प्रकार की सोची समझी साजिश के तहत किए जा रहे ईडी व आईटी के छापे बदले की भावना से किए जा रहे हैं। कांग्रेसी देश की आजादी के बलिदानियों के वंशज हैं जो अंग्रेजों की यातना सहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं। ईडी जैसी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं कांग्रेसी। रिजवी ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में बखूबी अपने फर्ज को अंजाम दे रही है। यह सरकार छत्तीसगढिया की, छत्तीसगढिया के द्वारा तथा छत्तीसगढिया के लिए विकास करने वाली सरकार है जो अडिग है तथा इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अगली सरकार छत्तीसगढिया की ही बनेगी, यह युनिवर्सल ट्रूथ है।

सरकार महाधिवेशन के तैयारी में व्यस्त और अपराधी अपराध करने में मस्त- शालिनी राजपूत

रायपुर। राजधानी रायपुर की गुढ़ियारी थाना के निकट एक युवती पर जानलेवा हमला और एक नाबालिग लड़की को सरेआम सड़क पर घसीटना इन सभी घटनाओं से छत्तीसगढ़ महतारी और उनकी बेटियां आहत है प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में व्यस्त हैं और अपराधी अपराध करने में मस्त हैं। प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है और प्रदेश में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है और राजधानी रायपुर अपराधपुर बन गया है। प्रदेश की हालात को सुधारने के बजाय, प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाए प्रदेश की सरकार कांग्रेस के होने वाले महाधिवेशन में पूरी पुलिस प्रशासन को लगा दिया है और प्रदेश को अपराधियों के अपराध करने के लिए छोड़ दिया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संभाली नहीं जा रही है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी क्योंकि एक महिला है सुश्री शैलजा कुमारी से मांग करते हैं कि महाधिवेशन से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों की सुरक्षा का जायजा ले कि छत्तीसगढ़ की महतारी बेटियों के साथ जो अन्याय और अपराध हो रहे हैं ।

कांग्रेस सरकार के दोहरे चरित्र के कारण नक्सल हिंसा बढ़ी- चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राजनांदगांव इलाके में फिर से नक्सल हिंसा की वारदातों में बढ़ोतरी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिन क्षेत्रों में भाजपा की सरकार ने नक्सल हिंसा पर काबू पा लिया था, वहां भी फिर से नक्सली वारदात क्यों हो रही हैं। यह कांग्रेस सरकार के नक्सलियों के प्रति लचर दृष्टिकोण का परिणाम है या यह सरकार नक्सलियों के सामने लाचार है?नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राजनांदगांव के बोरतलाब में नक्सली हमले में शहीद हुए दो पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कांग्रेस की संवेदनहीनता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि कांग्रेस के दो दर्जन से अधिक नेताओं ने प्रेस वार्ता कर भ्रष्टाचारियों के बचाव के लिए पैरवी की लेकिन नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार की ठोस नीतियों की वजह से पूरे देश में नक्सलवाद सिमट गया है लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के दोहरे चरित्र के कारण यहां नक्सलवाद के सफाए के लिए अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपने कर्तव्यों की जमीन पर शहीद हुए उन जवानों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते है तथा अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जवानों की शहादत को सैल्यूट करते है।

भाजपा नहीं, कांग्रेस डरी हुई है- अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस डरी हुई है। राज्य के 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने भाजपा विधानसभा घेराव करेगी। ईडी की जांच के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उसकी जांच सही दिशा में चल रही है और उसने इस जांच में जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, उसी के आधार पर जांच कार्रवाई आगे बढ़ी है। ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए अधिकारियों और अन्य लोगों को अब तक जमानत नहीं मिली है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस भी शहर में जाएं, कर्मचारी संगठन आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस सरकार को लेकर भयंकर आक्रोश है। यह सरकार डरी हुई है और अलोकतांत्रिक कदम उठा रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है, क्या उसमें कोई संपत्ति नहीं मिली है, क्या कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्या उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने कहा है कि बिना साक्ष्य के इनकी गिरफ्तारी हुई है?

23 से प्रारंभ होगा श्री धर्मनाथ जिनालय व जिनकुशल सूरी दादाबाड़ी प्रतिष्ठा महोत्सव

रायपुर। जैन समाज की आस्था का केंद्र धर्मनाथ जिनालय एवं जिनकुशल सूरी दादाबाड़ी का प्रतिष्ठा, अंजन शलाका, दीक्षा दशहानिका महोत्सव गुरुवार से प्रारम्भ हो रहा है। इस अतुलनीय कार्य के शुभारम्भ हेतु खारुन नदी से शुद्ध जल लाया जायेगा इस हेतु खारुन नदी के तट पर गुरुवार को जल विधान महोत्सव रखा गया है। 23 फरवरी को जैन समाज के श्रावक श्राविकाएं पवित्र जल लेने खारुन नदी जाकर जल विधान महोत्सव में शामिल होंगी। उधर महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जैन समाज के हर सदस्य के मन में इस प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भरपूर उत्साह है। हर शुभ कार्य की शुरूआत जल से ही होता है, इसलिए जल एकत्रीकरण भी विधान महोत्सव के बीच किया जायेगा। छत्तीसगढ़ के आंचल में बहती हुई खारुन माता के शुद्ध जल लेने हेतु महिलायें सूर्योदय के प्रथम प्रकाश में यह विधान करने जावेंगी। इन जलो को अलग अलग मिट्टी एवं धातु के घड़ों में भरकर कपूर आदि औषधियों व मंत्रोचार से पवित्र किया जायेगा और यही जल इस प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न विधान व अभिषेक के लिए उपयोग किया जायेगा।

2.65 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण और डेढ़ लाख से अधिक महिलाएं एनीमिया से हुई मुक्त

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य व पोषण के क्षेत्र में रच रहा है कीर्तिमान

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बीते चार साल के भीतर स्वास्थ्य और पोषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। हाल में ही राज्य सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन में मिलेट्स के व्यंजन को शामिल करने को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। बच्चों में कुपोषण दूर करने और किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को एनिमिया से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है। इस अभियान के बाद बच्चों के कुपोषण में 48 प्रतिशत की गिरावट आई है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में लगातार ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की नवाचारी योजनाओं मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, दाई-दीदी क्लिनिक, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, हमर लैब, मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ योजना का संचालन किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। छत्तीसगढ़ में लोगों को डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रूपए तक की इलाज की सुविधा दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना में 20 लाख रूपए तक की इलाज की सुविधा मिल रही है।

प्रदेश में 2.11 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण और एक लाख से अधिक महिलाएं एनीमिया से हुई मुक्त

मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू होने के समय वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4 लाख 33 हजार बच्चे कुपोषित थे। राज्य में अब तक 2 लाख 65 हजार से अधिक बच्चे कुपोषण मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार कुपोषित बच्चों की संख्या में 48 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य में कुपोषण की दर में 5.61 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत 32.1 प्रतिशत से कम है। अब तक डेढ़ लाख महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। इस योजना के तहत एनीमिया प्रभावितों को आयरन, फोलिक एसिड, कृमि नाशक गोलियां दी जा रही हैं।

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.